एक्ज़िम बैंक
EXIM BANK
भारतीय निर्यात–आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

एक्ज़िमिअस : निर्यात लाभ

मार्च 2013
VOL. XXVII ISSUE I

इस अंक में

6 'निर्यात वृद्धि के लिए' – भारत में चुनिंदा नीतिगत उपाय

7 एक्ज़िम बैंक की ऋण–व्यवस्थाएं

8 पिछली तिमाही

9 एक्ज़िम बैंक खबरों में

10 भारतीय रत्न एवं आभूषण बाजार के लिए उज्ज्वल संभावनाएं

11 वैश्विक निर्यात की तुलना में भारतीय निर्यात

12 पश्चिम आस्ट्रेलिया में निवेश अवसर

13 एक्ज़िम समाचार

14 देशों का सूक्ष्मावलोकन

15 मुद्रा प्रवृत्तियां

16 तीसरी दुनिया के देशों में व्यापार : अद्यतन प्रवृत्तियां

भारतीय निर्यात–आयात बैंक का तिमाही प्रकाशन
www.eximbankindia.in

पश्चिम अफ्रीका : अफ्रीकी वृद्धि गाथा का नायक

अफ्रीकी अर्थव्यवस्था समग्र रूप में द्रुत विकास की ओर अग्रसर है और विपुल आर्थिक संभाव्यता का संकेत दे रही है. उप–सहारीय अर्थव्यवस्थाएं विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में निरंतर तेजी से बढ़ रही हैं तथा कम से कम एक दर्जन अर्थव्यवस्थाओं ने पिछले छ: या इससे अधिक वर्षों में 6 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक की विकास दर दर्ज की है. संपत्ति अब रसूख वाले कुछ राजनीतिज्ञों की मुट्ठी में नहीं रह गयी है. आय वितरण में काफी सुधार हुआ है.

जैसा कि महाद्वीप में प्रवृत्ति रही है, पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र बेहतर भविष्य के संकेत दे रहा है. पश्चिम अफ्रीका द्वारा 2012 तथा 2013 में क्रमश: औसतन 6.9 प्रतिशत तथा 6.4 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर बनाये रखने की उम्मीद है.

कोत–दि–वॉर जो पश्चिम अफ्रीका का एक आर्थिक संवाहक है, तथा अब वर्षों से व्याप्त राजनीतिक ऊथल–पुथल से उबर रहा है. कोत–दि–वॉर का संकट से उबरना कई मामलों में एक बड़ा परिवर्तन है. उन्नत कारोबारी माहौल और निजी क्षेत्र का प्रोत्साहन तथा उत्पादन क्षमताओं को पुन: स्थापित करने के प्रयासों से अर्थव्यवस्था में 2013 में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है.

घाना अच्छी संभावनाएं दर्शा रहा है और 2020 तक मध्यम आय देश बनने के अपने लक्ष्य की दिशा में अच्छी प्रगति कर रहा है. हालिया वर्षों में आर्थिक वृद्धि दर लगातार 6 प्रतिशत से अधिक होने के फलस्वरूप घाना ने अपनी स्थूल अर्थव्यवस्था के प्रबंध को मजबूत बनाने में अच्छी प्रगति की है. राजकोषीय घाटा घटकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.3 प्रतिशत रह गया है. तेल राजस्व तथा कोकोआ और सोने के जोरदार निर्यात निष्पादन की बदौलत जीडीपी वृद्धि दर 2010 के 7.7 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर 2013 में 14 प्रतिशत तक हो जाने का अनुमान है (जिसमें से 7.5 प्रतिशत गैर–तेल से है). अगस्त 2011 में घाना की संसद ने इंफ्रास्ट्रक्चर का वित्तपोषण करने के लिए चायना डेवेलपमेंट बैंक (सीडीबी) से 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण अनुमोदित किया.

अफ्रीका की सबसे बड़ी संसाधनयुक्त अर्थव्यवस्था नाइजीरिया में बहु–विस्तारित सेवा क्षेत्र, यदि कृषि के साथ लिया जाए, अब तेल उत्पादन की लगभग बराबरी करता है. नाइजीरिया की आर्थिक वृद्धि पिछले दशक के दौरान औसतन लगभग 7.4 प्रतिशत वार्षिक रही है. तथापि आर्थिक वृद्धि से न तो गरीबी

चार्ट : पश्चिम अफ्रीकी देशों में जीडीपी वृद्धि दर, 2011–2012 (%)

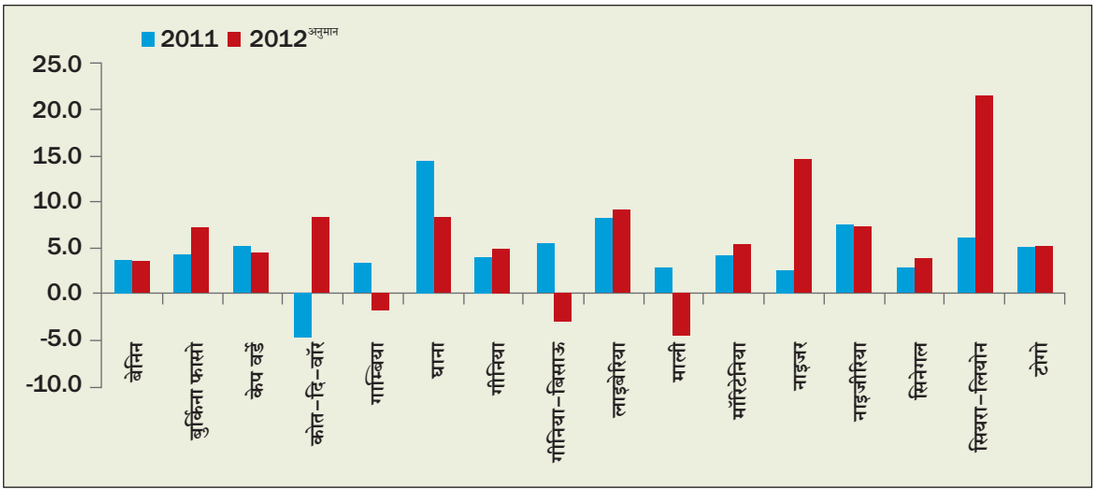

नोट : –अनुमान
सोत : वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), अक्तूबर 2012

कम हुई है और न ही रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं तथा बेरोजगारी की दर 24 प्रतिशत की उच्च दर पर बनी हुई है. अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर की जीर्ण-शीर्ण दशा और तेल एवं गैस उद्योग पर अधिक निर्भरता है.

घाना तथा नाइजीरिया राजकोषीय सुधार रणनीति का अनुसरण कर रहे हैं. पण्यों के निर्यात से उच्चतर आय की बदौलत इस रणनीति के क्रमिक रूप से फल मिल रहे हैं.

तथापि, यह देखा जा सकता है कि हाल की वृद्धि के लाभ अधिकांश देशों को अभी तक नहीं मिल रहे हैं. उपर्युक्त कुछ सफलताओं के बावजूद क्षेत्र के अधिकांश देश विकासपरक उद्देश्यों को पूरा करने में अब भी पीछे हैं. निजीकरण ने (अकेले नाइजीरिया में 100 से अधिक) कई देशों में शासन की भूमिका को कम किया है. यद्यपि पश्चिम अफ्रीका के भीतर फ्लाइट कनेक्शन में सुधार हो रहा है और क्षेत्रीय एकीकरण बढ़ रहा है जिससे सीमा पार माल तथा लोगों का आवागमन तो आसान हुआ है तथापि अवरोध बने हुए हैं और परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँच रहा है. ऐतिहासिक कारणों से अधिकांश पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र यूरोप और विशेषकर यूरो क्षेत्र के अत्यधिक प्रभाव में हैं. यूरोप तथा इस क्षेत्र के बीच सहबद्धता के कई चैनल हैं, जैसे व्यापार, कामगारों की आवा-जाही तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आदि. परिणामस्वरूप यूरोप में किसी भी प्रकार की मंदी/रूकावट इन चैनलों के माध्यम से इस क्षेत्र को भी प्रभावित करती है. चुनावों से जुड़ी अनिश्चितता एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है, विशेषकर तब जब हम पश्चिम अफ्रीका में आगामी वर्षों में होने वाले चुनावों की संख्या पर नज़र डालते हैं.

तथापि, तेल की नई खोजों और साथ ही विपुल खोजों की संभाव्यता के चलते निष्कर्षण क्षेत्र मजबूत बना हुआ है. इस क्षेत्र को खनन-क्षेत्र में तेजी का भी फायदा मिल रहा है क्योंकि पण्यों की कीमतों में तेजी बनी हुई है. सामान्य रूप में यहां वृद्धि व्यापक रही है और दूरसंचार तथा बैंकिंग उद्योगों में विस्तार के साथ निजी क्षेत्र का विश्वास बढ़ा है. इन सभी ने तीव्र वृद्धि और नये मध्यम वर्ग के विकास में योगदान दिया है.

यद्यपि, क्षेत्र के अधिकांश भागों में गंभीर आय असमानता अभी भी विद्यमान है किन्तु एक वास्तविक मध्य वर्ग का उभरना शुरू हो गया है. कुछ रिपोर्टों के अनुसार अब 60 मिलियन से अधिक अफ्रीकी घरों की वार्षिक आय बाजार विनिमय दरों पर 3000 अमरीकी डॉलर से अधिक है. 2015 तक इस संख्या के 100 मिलियन के स्तर पर पहुँच जाने का अनुमान है. उभरते उपभोक्ता वर्ग, अर्थात् वर्ष में 700 अमरीकी डॉलर से अधिक आमदनीवाले परिवारों की संख्या 300 मिलियन है. ये परिवार मोबाइल फोन का बिल दे सकते हैं तथा कुछ स्कूल फीस का खर्च दे सकते हैं हालांकि ये पश्चिमी मानकों के अनुसार मध्यम वर्ग में नहीं आ सकते हैं, पर वे एक बड़े बाजार का प्रतिनिधित्व करते हैं.

समग्र रूप में यह क्षेत्र विश्वभर में फैले अपने अप्रवासी नागरिकों से विप्रेषणों (रेमिटेंस) पर अत्यधिक निर्भर करता है. प्राइवेट ईक्विटी फंड विदेशी मुद्रा अंतर्वाह के महत्त्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं. पश्चिम अफ्रीका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) निवेशकों की धारणाओं में सुधार और क्षेत्र की सकारात्मक संभावनाओं के साथ पिछले दशक में तेजी से बढ़ा है. विश्व बैंक के अनुसार, अफ्रीका विश्व में सर्वाधिक निवेश प्रतिफल देने वालों में से एक है. पश्चिम अफ्रीका में निवेश 2010 के 11.3 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना 2011 में बढ़कर 13.3 बिलियन यूएस डॉलर हो गया. पिछले पांच वर्षों के दौरान, पश्चिम अफ्रीकी एफडीआई मुख्यत: पण्य सम्बद्ध निवेशों द्वारा संचालित रहा है. नाइजीरिया के तेल उद्योग और विशाल उपभोक्ता बाजार ने कुल 7.4 बिलियन यूएस डॉलर के निवेश के साथ इसे अंगोलिया को पछाड़ते हुए प्रांत का शीर्ष निवेश प्राप्तकर्ता बना दिया. तथापि, क्षेत्रीय निवेश में नाइजीरिया का हिस्सा घटकर लगभग 54 प्रतिशत (2005 में 79 प्रतिशत से) रह गया है क्योंकि घाना का नया तेल उद्योग तेजी से वृद्धि दर्ज कर रहा है जो 2007 में 860 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2011 में 1.7 बिलियन यूएस डॉलर के स्तर पर पहुँच गया है. नाइजीरिया के 'पेट्रोलियम उद्योग बिल' देश के तेल उद्योग की पारदर्शिता तथा अभिशासन को बढ़ाएगा. नाइजीरिया के व्यापार तथा निवेश मंत्रालय को तीन प्रमुख तेल कंपनियों से 4.5 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक राशि के निवेश की उम्मीद है. क्षेत्र में लगभग 70 प्रतिशत निवेश तेल एवं गैस क्षेत्र में जाता है, जबकि शेष की अधिकांश राशि रियल एस्टेट तथा दूरसंचार क्षेत्रों में जाती है.

पश्चिम अफ्रीका में भारतीय एफडीआई छोटे तथा मझौले उद्यमों सहित बड़ी भारतीय कंपनियों द्वारा भी किया गया है. हालांकि निवेश उद्योग के विविध खंडों जैसे तेल एवं गैस, कृषि कारोबार, इंफ्रास्ट्रक्चर, दूरसंचार, वित्तीय सेवाएं तथा हॉस्पीटलिटी में रहा है किन्तु वैश्विक रुझानों की तरह ही, इनमें से अधिकांश निवेश निष्कर्षण उद्योगों में हुए हैं. पण्यों (कमोडिटी) की कीमतों में सतत् वृद्धि और साथ ही देशी अर्थव्यवस्था में ऊर्जा और कच्चे माल की बढ़ती मांग इन कंपनियों के लिए प्रमुख प्रेरक शक्ति प्रतीत होती है. क्षेत्र में भारतीय निवेशों के अग्रणी लाभार्थी नाइजीरिया, घाना, गैबॉन तथा लाइबेरिया हैं.

उपर्युक्त सकारात्मक पहलुओं के बावजूद यहां का गरीब व्यक्ति अभी भी विकास के लाभों से वंचित है. गरीबों में व्याप्त असमानता एक बड़ा मुद्दा बन गया है क्योंकि इसमें जाति तथा धार्मिक आयाम भी शामिल हैं. नाइजीरिया में अलगाववादी समूह बोको हैराम द्वारा चलाई जा रही आतंकवादी गतिविधियों में हालिया वृद्धि से इसकी पुष्टि होती है. ये चुनौतियां असमानता को दूर करने में सरकार की क्षमता में बढ़ते अविश्वास से और विकट हो जाती हैं, जैसा कि ईंधन सब्सिडी को हटाने पर उपजे प्रतिरोध से पता चलता है जिसका

नाइजीरिया तथा घाना में मुख्यत: सम्पन्न वर्ग को फायदा मिलता है. नाइजीरिया में, राष्ट्रीय हड़ताल इसलिए हुई क्योंकि निर्धन वर्ग को उनके हितों की रक्षा करने की सरकार की क्षमता पर विश्वास नहीं है. परिणामस्वरूप, पश्चिम अफ्रीका में गरीबों तथा असुरक्षित लोगों की सहायता करने के लिए एक एकीकृत रणनीति तैयार करने तथा समानता के बारे में उभरती चिंताओं को समझना और उनका निराकरण करना नितांत आवश्यक है.

कृषि अब भी पश्चिम अफ्रीका में आर्थिक कार्यकलाप का केन्द्र बिन्दु बनी हुई है. इसमें 65 प्रतिशत से अधिक लोगों को रोजगार मिला है. जीडीपी में इसका 30-70 प्रतिशत योगदान है और निर्यात में भी इसका भारी हिस्सा है. कृषि में कंदों, मुख्यत: रतालू और कॅसावा जो मुख्य खाद्य पदार्थ हैं तथा नकदी फसलों जैसे कोकोआ, काजू और शी नट की प्रधानता है. यह क्षेत्र कुछ फसलों के उत्पादन में अग्रणी है. नाइजीरिया वर्तमान में कॅसावा का विश्व में अग्रणी उत्पादक है. कोत-दि-वॉर और घाना कोकोआ के विश्व में अग्रणी वैश्विक उत्पादक हैं तथा कोत-दि-वॉर और बेनिन कच्चे काजू के अग्रणी उत्पादक और निर्यातक हैं.

तथापि, प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर सूखे के फलस्वरूप मंद हो गई है. इसके साथ ही निम्न उत्पादकता, कमजोर नीतिगत माहौल, पट्टेदारी तथा उपयोग मुद्दों, फसल भंडारण की समस्या तथा विपणन आदि कुछ सामान्य चुनौतियां हैं जो क्षेत्र की वास्तविक संभाव्यता को बाधित करती हैं.

पश्चिम अफ्रीका कृषि में वृद्धि की संभाव्यता को फिर से तलाश रहा है. गीनिया बिसाऊ को छोड़कर पश्चिम अफ्रीकी देशों के आर्थिक समुदाय (इकोवास) में सभी सरकारों ने अफ्रीकी यूनियन के साथ व्यापक अफ्रीका कृषि कार्यक्रम(सीएएडीपी) समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं जिसमें सरकारों ने अपने बजट का कम से कम 10 प्रतिशत कृषि पर खर्च करने का वचन दिया है. हालांकि सरकारों ने इस वचनबद्धता को अभी तक पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया है किन्तु कई पारंपरिक विकास भागीदारों (जिनके साथ उभरते दक्षिण अर्थात् चीन, भारत तथा ब्राजील से विकास भागीदार जुड़ रहे हैं) ने इस क्षेत्र में सरकार के प्रयासों में समर्थन देने का वचन दिया है. 'अफ्रीका में हरित क्रांति हेतु गठजोड़' (एग्रा) एक अत्यधिक चर्चित विकास कार्यक्रम है जो अफ्रीका में हरित क्रांति लाने की दिशा में प्रयासरत है.

संभावनाएं

संपूर्ण महाद्वीप और विशेषकर पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र 2009 के वैश्विक संकट से उबर रहा है यद्यपि नई वैश्विक मंदी पुन: क्षेत्र की वृद्धि को बाधित कर रही है. यूरोप में गहराते संकट पर नज़र रखते हुए क्षेत्र को ऐसे सुधारों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जो वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं और सामाजिक तनाव कम करते हैं. अन्यथा इससे अरब स्प्रिंग जैसी क्रांति के दूसरे दौर को प्रोत्साहन मिलेगा. कोत-दि-वॉर में चुनावोत्तर संघर्ष से जीडीपी में लगभग 6 प्रतिशत संकुचन हुआ. कमजोर अंतर्राष्ट्रीय माहौल ने भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को हानि पहुँचाई. पश्चिम अफ्रीका सहित अफ्रीका ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं, जैसे चीन तथा भारत, जो अफ्रीका के व्यापार तथा निवेश के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, में अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि दर से लाभ उठाना जारी रखा है. हालांकि इससे क्षेत्र को अधिक समुत्थानशील बनने में सहायता मिल रही है किन्तु ये देश उन्नत देशों से उपजे प्रतिकूल प्रभावों की पूरी तरह से पूर्ति नहीं कर सकते हैं और इनका विकास भी हाल में मंद हुआ है. पण्यों की ऊँची कीमतों में गिरावट आयी है तथा कुछ कीमतों में अभी भी कमजोर मांग और वर्धित आपूर्ति के कारण और गिरावट आ सकती है. यूरोप के ऋण संकट के गहराने से इस क्षेत्र का निर्यात बाजार भी कमजोर होगा, पण्यों की कीमतों में मंदी आएगी और क्षेत्र के सुधारों को हानि पहुँचेगी.

पश्चिम अफ्रीका में एक्ज़िम बैंक

अफ्रीका के साथ द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंध बढ़ाने की भारत सरकार की रणनीति के अनुरूप और भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश के वित्तपोषण, संवर्धन तथा सुगमीकरण के लिए भारत में शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में, अफ्रीकी देश भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम भारत) के लिए फोकस क्षेत्र हैं. एक्ज़िम बैंक अफ्रीका में देशों के साथ भारत के व्यापार तथा निवेश संबंधों को बढ़ावा देने तथा सुगम बनाने के लिए वित्तपोषण, सलाहकारी तथा समर्थन कार्यक्रमों की एक व्यापक श्रृंखला चलाता है. इनमें वर्तमान में भारत सरकार की ओर से प्रवर्तनशील 44 ऋण-व्यवस्थाएं, भारतीय परियोजना निर्यात के लिए 3 सीधी ऋण-व्यवस्थाएं, संयुक्त उद्यम लगाने वाली कंपनियों के लिए सहायता और अफ्रीकी संस्थाओं के साथ सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना शामिल है.

बैंक 'एक्ज़िम बैंक-सीआईआई भारत-अफ्रीका परियोजना भागीदारी सम्मेलन' का मुख्य भागीदार है जिसका भारत में प्रत्येक वर्ष आयोजन किया जाता है. भारत-अफ्रीका परियोजना भागीदारी पर 9वाँ सीआईआई-एक्ज़िम बैंक सम्मेलन नई दिल्ली में 17-19 मार्च, 2013 के दौरान आयोजित किया गया था.

डकार, सिनेगल में एक्ज़िम बैंक का प्रतिनिधि कार्यालय पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र के साथ आर्थिक सहयोग को सुगम बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. यह प्रतिनिधि कार्यालय विभिन्न संस्थाओं जैसे अफ्रीकी विकास बैंक, इकोवास बैंक फार इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट (ईबीआईडी), वेस्ट अफ्रीकन डेवेलपमेंट बैंक (बीओएडी) और क्षेत्र में भारतीय दूतावास के साथ परस्पर संपर्क में रहता है.

4 कारोबार अवसर तथा प्राप्त संविदाएं

मार्च 2013 को नई परियोजनाएं

देश/ निष्पादक एजेंसी	परियोजना/संक्षिप्त कार्यक्षेत्र	निधीयन एजेंसी से ऋण
मेकले शहर जल एवं मद जल निकासी सेवा प्रबंधक का कर्यालय, पहली मंज़िल पो. बॉ. : 266 मेकले इथियोपिया **संपर्क:** श्री एटो गिडेना एबेब यूटिलिटी मैनेजर टेली : +251 344 404380 फैक्स : +251 334 411000 ई-मेल : gidab71@yahoo.com	**शहरी जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना** परियोजना में पाइपों तथा फिटिंग्स का प्रापण (प्रोक्योरमेंट) शामिल है:- लॉट 1: यूपीवीसी पाइप एवं फिटिंग्स (5,214 मीटर) लॉट 2: डीसीआई पाइप एवं फिटिंग्स (18,159 मीटर)	**विश्व बैंक** 100 मिलियन यूएस डॉलर
जल विकास एवं सिंचाई मंत्रालय **शिरे नदी घाटी प्रबंधन कार्यक्रम** (चरण-1) परियोजना, एडीएल हाउस, एसआरबीएमपी परियोजना कार्यालय, दूसरी मंज़िल, पो. बॉ. 30242 राजधानी शहर, लिलांग्वे मालावी **संपर्क:** आंतरिक प्रापण समिति के अध्यक्ष टेली : +2651 774 252 फैक्स : +2651 774 253 ई-मेल : shirebasin@gmail.com	**शिरे नदी घाटी प्रबंध प्रोग्राम** परामर्शी सेवा का प्राथमिक उद्देश्य तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन प्रदान करना और निर्माण कार्य जैसे आवास इकाई, कार्यालय भवन तथा घरेलू जल आपूर्ति का पर्यवेक्षण करना है. लेनग्वे नेशनल पार्क में इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन और निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण को शिरे नदी घाटी प्रोग्राम के अंतर्गत सहायता दी जा रही है.	**विश्व बैंक** 125 मिलियन यूएस डॉलर
म्युनिसिपल कंपनी निप्रोपेट्रोवस्क मेट्रो 8, कुर्चाटोवा स्ट्रीट निप्रोपेट्रोवस्क 49038 उक्रेन **संपर्क:** श्री विक्टर सिटोनिन कंपनी के निदेशक टेली : +380 562 42 37 68 फैक्स : +380 56 778 65 33 ई-मेल : metro@dniprorada.gov.ua	**नेप्रोपेट्रोवस्क मेट्रो निर्माण पूर्णता परियोजना** परियोजना का उद्देश्य शहरी परिवहन मज़बूत करने की समग्र रणनीति के हिस्से के रूप में वर्तमान मेट्रो प्रणाली को विस्तारित करना और नेप्रोपेट्रोवस्क में सार्वजनिक परिवहन में सुधार लाना है.	**यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक** € 45.5 मिलियन
अर्मेनियम वॉटर एंड सिवरेज सीजेएससी वर्दानांट्सब्लाइड ऐले, 3री मंज़िल 0010 येरेवन अर्मेनिया गणराज्य **संपर्क:** श्री नॉरिक गेवोरग्यान आईपीसीडी के निदेशक टेली : +374 10 54 28 77 फैक्स : +374 10 54 28 77 ई-मेल : ngevorgyan@armwater.am	**अर्मेनियाई लघु नगरपालिका जल परियोजना** परियोजना में निम्न के लिए डिज़ाइन, आपूर्ति, संस्थापन, प्लांट की कमीशनिंग और निर्माण कार्य शामिल हैं : • दिलीजान में यांत्रिक मद जल ट्रीटमेंट संयंत्र • जरमुक में यांत्रिक मद जल ट्रीटमेंट संयंत्र	**यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक** € 8.5 मिलियन
दक्षिण वियतनाम बिजली परियोजना प्रबंधन बोर्ड (एसपीएमबी) 383 वो वैन कीट स्ट्रीट, जिला-1, होचीमिन्ह शहर वियतनाम **संपर्क:** श्री गुयेन तियन हई निदेशक टेली : +8482 210 0719 फैक्स : +8483 836 1096 ई-मेल : mynt@npt.evn.vn	**एमएफएल बिजली पारेषण निवेश कार्यक्रम, श्रृंखला 2** 220 केवी काऊ बोंग-डक होवा पारेषण लाइन और 220 केवी काऊ बोंग-हॉक मॉन-बिन्ह टैन ट्रान्समिशन लाइन के लिए कंडक्टर, ऑप्टिकल ग्राउंड वायर, अर्थ वायर, इन्सुलेटर तथा एक्सटेंशन बे उपकरण - उनकी फिटिंग्स तथा सहायक पुरजों सहित - की आपूर्ति और सुपुर्दगी हेतु संविदा.	**एशियाई विकास बैंक** 110.2 मिलियन यूएस डॉलर

देश/ निष्पादक एजेंसी	परियोजना/संक्षिप्त कार्यक्षेत्र	निधीयन एजेंसी से ऋण
ढाका जल आपूर्ति क्षेत्र विकास परियोजना 98 काजी नजरूल इस्लाम एवेन्यू कवरान बाजार, 8वीं मंज़िल, डब्ल्यूएएसए भवन ढाका: 1215 बांग्लादेश **संपर्क:** श्री मोहम्मद शाहजहाँ अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर एवं परियोजना निदेशक टेली : 8802 9116033 फैक्स : 8802 9116086 ई-मेल : pddwssdp@gmail.com	**ढाका जल आपूर्ति क्षेत्र विकास परियोजना** निम्नलिखित रूप में विशेष वॉल्व (प्रेशर-सह, प्रेशर कमी वॉल्व तथा वायु निर्मोचन वॉल्व) का प्रापण :- 1. प्रेशर सस्टेनिंग वॉल्व - 126 नग 2. प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व - 67 नग 3. एकल छिद्र वायु निर्मोचन वॉल्व - 80 नग 4. द्वि-छिद्र वायु निर्मोचन वॉल्व - 150 नग	**एशियाई विकास बैंक** 150 मिलियन यूएस डॉलर
इथियोपिया इलेट्रिक पॉवर कार्पोरेशन (ईईपीसीओ) कार्पोरेट प्रापण तथा लेखा कार्यालय डब्ल्यू/सिनेबेट डिगॉल स्क्वेयर पो. बॉ. 1233, अदिस अबाबा, इथियोपिया तथा **केन्या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (केईटीआरएसीओ)** इथियोपिया - केन्या पॉवर सिस्टम इंटरकनेक्शन परियोजना कार्यालय, दूसरी मंज़िल, कैपिटल हिल स्क्वेयर अपर हिल, पो. ऑ. बॉ. 34942-00100 नैरोबी, केन्या **संपर्क:** इथियोपिया टेली : +251 111 560027 फैक्स : +251 111 550822 तथा केन्या टेली : +254 20 4956000 फैक्स : +254 20 4956010	**पूर्वी विद्युत राजमार्ग परियोजना** इथियोपिया तथा केन्या में अलग-अलग संविदाओं के अंतर्गत लगभग 200 किमी. प्रत्येक के पांच लॉटों में विभाजित ओपीजीडब्ल्यू के साथ 1045 किमी, ± 500 केवी एचवीडीसी ओवरहेड ट्रान्समिशन लाइन की डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थल पर स्थापना, परीक्षण तथा कमिशनिंग.	**अफ्रीकी विकास बैंक** 1.26 मिलियन यूएस डॉलर
रोपवेज़ ट्रान्सपोर्ट लिमिटेड 1 डी, क्लब रोड, आईकोई, लागोस नाइजीरिया **संपर्क:** कैप्टन डैपो ओलुमिड सीईओ/प्रबंध निदेशक टेली : +2340 18447797 ई-मेल : rtl@ropewaystransport.com	**लागोस केबल कार पारगमन (एलसीसीटी) परियोजना** लागोस, नाइजीरिया में यात्रियों के लिए केबल कार रोपवे (रज्जुमार्ग) का विकास, जिसमें ट्राई-केबल वियोज्य ग्रिप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए तीन लाइनें शामिल हैं.	**अफ्रीकी विकास बैंक** 500 मिलियन यूएस डॉलर

भारतीय कंपनियों/परामर्शदाताओं को प्राप्त चुनिंदा संविदाएं

लार्सन एंड टूब्रो लि., मुंबई	**एशियाई विकास बैंक** से सहायता प्राप्त - बांग्लादेश की गैस पारेषण तथा विकास परियोजना के अंतर्गत पाइपलाइनों के लिए डिज़ाइन, निर्माण तथा टर्नकी आपूर्ति, संस्थापन, निर्माण, परीक्षण तथा कमिशनिंग और पश्चिम क्षेत्र एससीएडीए सिस्टम के परिचालन एवं रखरखाव हेतु संविदा.
कल्पतरु पॉवर ट्रांसमिशन लि., गांधीनगर और ज्योति स्ट्रक्चर्स लि., मुंबई	**एशियाई विकास बैंक** से सहायता प्राप्त - तज़ाकिस्तान की क्षेत्रीय बिजली पारेषण परियोजना के लिए लॉट 1 - 220 केवी ओवरहेड ट्रान्समिशन लाइन और 220 केवी उप-स्टेशन विस्तार के लिए टर्नकी संविदा.
न्युकॉन स्विचगियर प्रा. लि., लुधियाना	**विश्व बैंक** समूह से सहायता प्राप्त - केन्या की ऊर्जा क्षेत्र सुधार परियोजना के लिए वितरण ट्रान्सफॉर्मरों की आपूर्ति हेतु संविदा.
सिप्ला लि., मुंबई	**विश्व बैंक** समूह से सहायता प्राप्त - इथियोपिया की पोषण परियोजना के लिए औषधियों की आपूर्ति हेतु संविदा.
लवली ऑफसेट प्रिंटर्स प्रा. लि., शिवकाशी	**विश्व बैंक** समूह से सहायता प्राप्त - वियतनाम एस्क्यूला न्यूवा परियोजना के पूर्वोत्तर प्रांत तथा शिक्षा एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के लिए ग्रेड 2 एंड 3 लर्निंग गाइड तथा प्रयोक्ता मैनुअल की प्रिंटिंग तथा प्रावधान हेतु संविदा.
एंजलिक इंटरनेशनल लि., नोएडा	**विश्व बैंक** समूह से सहायता प्राप्त - सेंट्रल क्षेत्र (माकुलुलु, चेल्स्टॉन तथा वोर्नावैली) में जाम्बिया के विद्युत परियोजना में वृद्धि के लिए ग्रिड इंटेन्सीफिकेशन कार्य हेतु संविदा.
टेक्नोफैब इंजीनियरिंग लि., फरीदाबाद तथा गैमन इंडिया लि., मुंबई	**विश्व बैंक** समूह से सहायता प्राप्त - जिम्बाब्वे की अत्यावश्यक जल आपूर्ति तथा स्वच्छता पुनर्वास परियोजना के लिए प्राप्त संविदा.

6

'निर्यात वृद्धि के लिए' – भारत में चुनिंदा नीतिगत उपाय

भारत अपने दीर्घावधि लक्ष्यों को प्राप्त करने और समग्र आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने हेतु व्यापार नीति का सक्रिय रूप से प्रयोग करता है. भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति के वार्षिक अनुपूरक, केन्द्रीय बजट 2013-14 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक एवं ऋण नीति में मुख्यत: निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई उपायों की घोषणा की है.

5 जून, 2012 को जारी विदेश व्यापार नीति के वार्षिक अनुपूरक में घोषित नीतिगत उपाय:

- *निर्यात संवर्धन पूँजीगत माल योजना (ईपीसीजी)* : शून्य शुल्क ईपीसीजी योजना को 31 मार्च, 2013 तक विस्तारित कर दिया गया है और शून्य शुल्क ईपीसीजी योजना के दायरे को बढ़ाया गया है. पूर्वोत्तर राज्यों से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ईपीसीजी योजना के अंतर्गत निर्यात दायित्व सामान्य निर्यात दायित्व का 25 प्रतिशत है और इस क्षेत्र में अधिसूचित स्थल सीमा शुल्क केन्द्रों के माध्यम से निर्दिष्ट उत्पादों के निर्यात को एफओबी मूल्य के 1 प्रतिशत की सीमा तक अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा.

- *हरित प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यात हेतु सहायता :* अभिनिर्धारित 16 हरित प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, ईपीसीजी योजना के अंतर्गत इन उत्पादों के विनिर्माण के लिए निर्यात दायित्व सामान्य निर्यात दायित्व का 75 प्रतिशत तक कर दिया गया है.

- *कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु सहायता :* आईटीसी (एचएस 1-24) के अंतर्गत स्टेटस होल्डर उत्पादों का निर्यात करने वालों को इस प्रकार निर्यात किये जाने वाले कृषि उत्पादों के एफओबी मूल्य के 10 प्रतिशत के समतुल्य ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप प्रदान किया जाता है.

- *बाजार एवं उत्पादन विविधीकरण :* फोकस बाजार योजना (एफएमएस) और विशेष फोकस बाजार योजना (विशेष एफएमएस) प्रत्येक में सात नये बाजार शामिल किये गये हैं. बाजार सम्बद्ध फोकस उत्पाद योजना (एमएलएफपीएस) में छियालीस नई मदें शामिल की गई हैं और इसे यूएसए और यूरोपीय संघ को एचएस 61 व 62 के निर्यात के लिए विस्तारित किया गया है. फोकस उत्पाद योजना की सूची में 110 नई मदें शामिल की गई हैं. विशेष कृषि तथा ग्राम उद्योग योजना में दो नई मदें शामिल की गई हैं. विदेश व्यापार नीति अनुपूरक 2012-13 के अलावा, दिसंबर 2012 में व्यापार सुगमीकरण उपाय के रूप में घोषित अतिरिक्त उपायों के तहत एफएमएस में 5 नये उत्पाद, विशेष एफएमएस में एक नया बाजार, एमएलएफपीएस में 62 नई मदें और 3 देश और एफपीएस में 102 नई मदें 1 जनवरी, 2013 से शामिल की गई. विशेष कृषि तथा ग्राम उद्योग योजना के लिए, शेलाक-मोम, तिलहनों या 51 प्रतिशत से अधिक प्रोटीन रखने वाले जंगली फलों के आटे तथा आहार और अन्यत्र निर्दिष्ट न किये गए खाद्य संपाक को शामिल किया गया है.

- *प्रक्रिया का सरलीकरण :* डाक या कुरियर या ई-कॉमर्स के माध्यम से दिल्ली व मुंबई से निर्यात एफटीपी के अंतर्गत निर्यात लाभ के लिए पात्र हैं.

- *सिंथेटिक वस्त्रों के निर्यात के लिए सजावटों का नि:शुल्क आयात :* हथकरघा, सूती तथा पॉलिएस्टर वस्त्रों के निर्यात पर सजावटों के नि:शुल्क आयात की अनुमति है.

- *नई 'ई-बीआरसी' पहल :* ईडीआई के अंतर्गत एक प्रमुख पहल 'ई-बीआरसी' का शुभारंभ किया जो संबंधित बैंकों से डीजीएफटी के सर्वर को दैनिक आधार पर विदेशी मुद्रा प्राप्तियों का इलेक्ट्रॉनिक पारेषण संभव बनायेगा. निर्यातकों को बैंक निर्यात तथा वसूली प्रमाणपत्र (बीआरसी) जारी करने के लिए बैंक से कोई अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं है.

- *वृद्धिशील निर्यात पर प्रोत्साहन :* यह प्रोत्साहन आईईसी कोड धारक को आधार अवधि जनवरी-मार्च 2012 की तुलना में जनवरी-मार्च 2013 के दौरान यूएसए, यूरोपीय संघ तथा एशियाई देशों को किये गए निर्यात की वृद्धिशील वृद्धि पर 2 प्रतिशत की दर से मंजूर किया जाएगा.

केन्द्रीय बजट 2013-14 में जूते सहित चमड़े तथा चमड़े के सामान के निर्यात के लिए निर्दिष्ट मशीनों पर शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने और कीमती रत्नों तथा अर्ध कीमती रत्नों के पूर्व-रूप पर शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है. इसमें तेल निष्कर्षित धान की भूसी की खली पर वापसी निर्यात शुल्क का भी प्रस्ताव है. इसमें अब सिनवैट मार्ग के अलावा यार्न, फैब्रिक तथा वस्त्र चरणों में कपास तथा मानव निर्मित क्षेत्र (स्पून यार्न) के लिए, 'शून्य उत्पाद शुल्क मार्ग' को बहाल किया गया है. कपास के मामले में, बजट में प्रस्ताव किया गया है कि फाइबर चरण में शून्य शुल्क होगा और स्पून यार्न के मामले में फाइबर चरण में 12 प्रतिशत शुल्क होगा. बजट के अनुसार हस्त-निर्मित कालीन तथा कॉयर या जूट के टेक्सटाइल फ्लोर कवरिंग और पोत एवं जलयान का निर्यात उत्पाद शुल्क से मुक्त होगा.

ऋण प्रवाह को नियंत्रित करने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित निर्यात नीति उपायों में शामिल हैं :

- नवम्बर 2011 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने ईसीबी की 3-5 वर्ष की परिपक्वता अवधि के लिए समस्त लागत की उच्चतम सीमा बढ़ाकर 6 महीने के लिबोर/ यूरो लिबोर/ यूरोबोर से 350 आधार बिन्दु तथा 5 वर्ष से अधिक की परिपक्वता के लिए 500 आधार बिंदु अधिक कर दी. इस उच्चतम सीमा को 31 मार्च, 2013 तक बढ़ा दिया गया है.

- निर्यातकों को निधियों की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से बैंकों को विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर अपनी ब्याज दर का निर्धारण करने की अनुमति है.

- निर्यात क्षेत्र को ऋण-प्रवाह बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) सुविधा की पात्र सीमा को पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया निर्यात ऋण के 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है. पुनर्वित सुविधा पर प्रभारित ब्याज दर को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत प्रचलित रेपो दर पर बनाये रखा गया.

- 2 प्रतिशत ब्याज सहायता योजना, जो पहले सिर्फ हैंडलूम, हस्तशिल्प, कालीन तथा एसएमई के लिए थी, को कई अन्य श्रम गहन क्षेत्रों के लिए भी विस्तारित किया गया. इसे 31 मार्च 2014 तक पुन: बढ़ा दिया गया और इसके अंतर्गत इंजीनियरिंग माल की 134 टैरिफ मदें भी शामिल की गईं.

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने म्यांमार, सार्क देशों और अफ्रीकी क्षेत्र के देशों के लिए एक्ज़िम बैंक के माध्यम से परियोजना निर्यात के लिए 2 प्रतिशत ब्याज सहायता की एक 'प्रायोगिक योजना' भी शुरू की है.

एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएं

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने लघु एवं मझौले उद्यमों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के साथ प्रभावी बाज़ार प्रवेश व्यवस्था के रूप में ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करने पर विशेष बल दिया है. एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, सॉवरिन सरकारों और अन्य विदेशी संस्थाओं को उन देशों के क्रेताओं को भारत से आस्थगित ऋण शर्तों पर विकासपरक और बुनियादी परियोजनाएं, उपकरण, माल एवं सेवाएं आयात करने के लिए ऋण-व्यवस्थाओं की सुविधा प्रदान करता है. भारतीय निर्यातक बिना दायित्व के शिपिंग दस्तावेजों के परक्रामण पर एक्ज़िम बैंक से पात्र राशि का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं. एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के आदेश पर भी ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है. सरकार के आदेश पर प्रदान की जाने वाली ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत एक्ज़िम बैंक भारतीय निर्यातकों को माल के शिपिंग पर अपफ्रंट संविदा मूल्य की 100 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति करता है बशर्ते कि कुल संविदा मूल्य का कम से कम 75 प्रतिशत माल एवं सेवाएं भारत से मंगायी जानी चाहिए. एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएं भारतीय निर्यातकों को जोखिम रहित, दायित्व रहित निर्यात वित्तपोषण का विकल्प प्रदान करती हैं.

एक्ज़िम बैंक द्वारा अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, यूरोप, ओशिनिया और सीआईएस के 73 देशों को शामिल करते हुए वर्तमान में 8.69 बिलियन यूएस डॉलर की ऋण वचनबद्धताओं के साथ 168 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की गई हैं जो भारत से निर्यात के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं. इन ऋण-व्यवस्थाओं ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, परिवहन, संचार, विनिर्माण, ऊर्जा उत्पादन तथा पारेषण, ग्रामीण विद्युतीकरण में परियोजनाओं के निर्यात को उत्प्रेरित किया है. भारतीय परियोजना निर्यातों के वित्तपोषण के लिए प्रदान की जा रही ऋण-व्यवस्थाएं प्राप्तकर्ता देश में विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारतीय विशेषज्ञता और परियोजना निष्पादन क्षमताओं का प्रदर्शित करती हैं. मुख्यत: विकासशील देशों को भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई ऋण-व्यवस्थाएं आज बाजार प्रवेश का एक प्रभावी साधन बन चुकी हैं और अफ्रीका तथा अमेरिकी देशों के अब तक अदोहित क्षेत्र के लिए एक सोपान बन गई हैं.

एक्ज़िम बैंक ने भारत सरकार के आदेश एवं सहयोग से जनवरी-मार्च 2013 तिमाही के दौरान निम्नलिखित ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की हैं :

- कॉमोरोस की राजधानी मोरोनी में 18 मेगावॉट की बिजली परियोजना की स्थापना के लिए कॉमोरोस को 41.60 मिलिन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था.
- बुर्किनो फासो में किफायती आवास और किफायती भवनों के वित्तपोषण के लिए बुर्किना फासो सरकार को 22.50 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था. एक्ज़िम बैंक इसके पहले बुर्किना फासो को दो ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान कर चुका है. 30 मिलियन यूएस डॉलर की पहली ऋण व्यवस्था बुर्किना फासो में ट्रैक्टरों, हार्वेस्टरों और कृषि प्रसंस्करण उपकरणों के अर्जन के वित्तपोषण के लिए प्रदान की गई थी जबकि 25 मिलियन यूएस डॉलर की दूसरी ऋण-व्यवस्था का उपयोग बुर्किना फासो में ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के लिए किया जा रहा है.

कृपया अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :

श्रीमती गीता पूजारी
महाप्रबंधक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
सेन्टर एक बिल्डिंग, 21वीं मंज़िल
विश्व व्यापार केन्द्र कॉम्प्लेक्स
कफ़ परेड
मुंबई- 400 005

फोन : (022) 22162073
(022) 22172310
फैक्स : (022) 22182460
ई-मेल : eximloc@eximbankindia.in

एनईआईए के अंतर्गत क्रेता ऋण

एक्ज़िम बैंक ने भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. (ईसीजीसी) के साथ मिलकर भारत सरकार के राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता योजना (एनईआईए) के अतंर्गत क्रेता ऋण नामक एक नई योजना प्रारंभ की है. इसके अंतर्गत बैंक विदेशी सॉवरिन सरकारों और सरकार के स्वामित्व वाली संस्थाओं को आस्थगित भुगतान शर्तों पर भारत से माल तथा सेवाओं के आयात के लिए ऋण सुविधा प्रदान कर भारत से परियोजना निर्यात का वित्तपोषण करता है और निर्यात को सुगम बनाता है. यह भारतीय निर्यातकों को दायित्व-रहित वित्तपोषण विकल्प का एक सुरक्षित तरीका प्रदान करता है और विकासशील देशों में पारंपरिक तथा नए बाजारों जिन्हें मध्यम या दीर्घावधि आधार पर आस्थगित ऋण की आवश्यकता होती है, प्रवेश के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में कार्य करता है.

एक्ज़िम बैंक की वेबसाईट पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्रेता ऋण की प्रमुख विशेषताएं (www.eximbankindia.in/neia.pdf), उसमें वर्तमान में शामिल देशों की सूची (www.eximbankindia.in/ neia-list.pdf) और समुद्रपारीय उधारकर्ताओं द्वारा देय वर्तमान ब्याज दरों (www.eximbankindia.in/ bc-interest.pdf) का विवरण उपलब्ध है.

एक्ज़िम बैंक द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत 291 मिलियन यूएस डॉलर (लगभग ₹ 1600 करोड़) मूल्य की तीन परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है. इसके अलावा एक्ज़िम बैंक ने अफ्रीका, सार्क, आसियान, मध्य एशिया तथा पूर्वी यूरोप के देशों को शामिल करते हुए कुल 5 बिलियन यूएस डॉलर (₹ 27,500 करोड़ के समतुल्य) राशि की 70 से अधिक परियोजनाओं को सहायता देने के लिए सिद्धांत रूप में वचनबद्धता दी है.

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रेपो दर में 0.25% कटौती

भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा वृद्धि को प्रोत्साहित करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए 19 मार्च, 2013 को अपनी अल्पावधि उधार दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की गई किन्तु उच्च खाद्य मुद्रास्फीति और चालू खाता घाटे के कारण ब्याज दरों में और नरमी न करने की चेतावनी भी व्यक्त की गई है. भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति की मध्य तिमाही समीक्षा में कहा है कि अर्थव्यवस्था को उच्च वृद्धि की पटरी पर वापस लाने में मुख्य चुनौती निवेशों को बढ़ावा देना है. इसके लिए प्रतिस्पर्धी ब्याज दर आवश्यक है किन्तु पर्याप्त नहीं है; तद्नुसार रिज़र्व बैंक ने अपनी अल्पावधि उधारी दर या रेपो दर को 0.25 प्रतिशत घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया; दो महीने में यह दूसरी लगातार कटौती है.

वाणिज्य मंत्रालय ने थाईलैंड से स्वर्ण आभूषणों का आयात बंद किया

बढ़ते चालू खाता घाटे को देखते हुए वाणिज्य विभाग ने राजस्व विभाग को कहा है कि जब तक थाईलैंड द्वारा जारी किये गए उद्गम-प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नहीं हो जाता है, तब तक अर्ली हार्वेस्ट स्कीम के प्रावधानों के अंतर्गत थाईलैंड से स्वर्ण आभूषणों के आयात को बंद रखते हुए अधिसूचना जारी करे. भारत सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है. यह मांग मुख्यत: आयात द्वारा पूरी की जाती है. थाईलैंड से स्वर्ण आभूषणों के आयात पर अर्ली हार्वेस्ट स्कीम, जो एक द्विपक्षीय व्यापार करार है, के अंतर्गत 1 प्रतिशत का रियायती शुल्क लगता है, जबकि अन्य देशों से स्वर्णाभूषणों के आयात पर 10 प्रतिशत कर लगता है. इस निलंबन से चालू खाता घाटे को कम करने में सहायता मिलने की उम्मीद है.

आरबीआई पैनल ने समान खाता संख्या संरचना की सिफारिश की

आरबीआई पैनल ने सिफारिश की है कि 26 अंकीय अंतर्राष्ट्रीय बैंक खाता संख्या (आईबीएएन) फॉर्मेट का इस्तेमाल भारतीय बैंकों में भी किया जाना चाहिए. आईबीएएन बैंकों में लेन-देनों के बारे में सूचना रखने वाली एक समान प्रणाली है ताकि परिशुद्धता और गति सुनिश्चित की जा सके. यह जमा (क्रेडिट) को गलत खाते में जाने से रोकता है और प्रोसेसिंग के माध्यम से इसे सीधे सुगम बनाता है. आईबीएएन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंक खातों की पहचान करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है. फॉर्मेट में 26 अंक अर्थात् 18 अंकीय बैंक खाता संख्या, 4-अंकीय बैंक कोड, 2-अंकीय देश कोड और 2 चेक डिजिट शामिल हैं.

आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेशन बांडों में एफआईआई सीमा बढ़ायी

बांड बाजार में विदेशी निधियां आकर्षित करने के लिए आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूतियों तथा कॉर्पोरेट बांडों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की धारिता के लिए अधिकतम सीमा को 5 बिलियन यूएस डॉलर कर बढ़ा दिया गया है. देशी ऋण पर उच्चतम सीमा अब 75 बिलियन यूएस डॉलर है. सरकारी प्रतिभूतियों में एफआईआई द्वारा निवेश के लिए 10 बिलियन यूएस डॉलर की उप-सीमा 5 बिलियन यूएस डॉलर बढ़ायी गई, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को छोड़कर कॉर्पोरेट ऋण पर उच्चतम सीमा 20 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़ाकर 25 बिलियन यूएस डॉलर कर दी गई.

भारत तथा दक्षिण अफ्रीका पीटीए पर अग्रसर

केन्द्रीय वाणिज्य, उद्योग और कपड़ा मंत्री श्री आनंद शर्मा और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के व्यापार एवं उद्योग मंत्री रॉब डैविस ने मध्य जनवरी 2013 में जोहॉन्सबर्ग में भारत-दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क यूनियन (एसएसीयू) अधिमान्य व्यापार करार (पीटीए) की समीक्षा की. दोनों मंत्रियों ने भारत-एसएसीयू पीटीए को शीघ्र अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की. श्री आनंद शर्मा ने श्री डैविस से अनुरोध किया कि वे भारत-एसएसीयू पीटीए वार्ता के मुद्दे को उठाएं और पीटीए में औसत अधिमान्य मार्जिन (एमओपी) के बारे में भारत के प्रस्ताव पर एसएसीयू का उत्तर शीघ्र भिजवाएं ताकि दोनों पक्ष तद्नुसार उसे अंतिम रूप दे सकें और टैरिफ अनुरोध सूचियों पर अपने उत्तर का आदान-प्रदान कर सके तथा इस प्रकार बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके.

उभरती अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक वृद्धि की संवाहक होंगी – श्री आनंद शर्मा

केन्द्रीय वाणिज्य, उद्योग एवं कपड़ा मंत्री श्री आनंद शर्मा ने जनवरी 2013 में आगरा में आयोजित साझेदारी शिखर सम्मेलन में ''बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं : विश्व के नये वृद्धि केन्द्र'' विषयक सत्र के दौरान अपना मुख्य भाषण देते हुए कहा कि भारत जैसे देश के लिए उच्च वृद्धि दर को बनाए रखना एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक सामाजिक अनिवार्यता है, क्योंकि सिर्फ सतत् आर्थिक वृद्धि से ही हम लाखों लोगों को गरीबी के जाल से निकाल सकते हैं. श्री शर्मा का अभिमत था कि विश्व भर में देशों के समक्ष आर्थिक चुनौतियों के बावजूद उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं ने पिछले दो दशकों के दौरान शुरू किये गये उदार आर्थिक सुधारों की बदौलत महत्त्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है. एक्ज़िम बैंक ने भी इस साझेदारी शिखर सम्मेलन में भाग लिया था.

नये बैंक लाइसेंसों पर अंतिम मानदंड शीघ्र : रिज़र्व बैंक के उप गर्वनर

श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुष्टि की है कि भारतीय रिज़र्व बैंक नये बैंक लाइसेंस जारी करने के बारे में अंतिम दिशानिर्देश शीघ्र ही जारी करेगा. प्रारूप दिशानिर्देशों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक द्वारा प्रायोजित न की गई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए पूँजी एक्सपोजर के लिए 150 प्रतिशत और वाणिज्यिक रियल एस्टेट एक्सपोजर के लिए 125 प्रतिशत का जोखिम भारत प्रस्तावित किया है. इसमें कठोर प्रवेश बिन्दु मानदंड और एनबीएफसी के लिए 7.50 प्रतिशत तथा इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण कंपनियों के लिए 10 प्रतिशत का टियर-I पूँजी पर्याप्तता मानदंड का भी प्रस्ताव है.

एक्ज़िम बैंक ने आरटीबीआई के साथ सहयोग ज्ञापन करार पर हस्ताक्षर किये

एक्ज़िम बैंक ने कंपनियों का मूल्यांकन करने और उनकी प्रारंभिक चरण में सहायता करने के लिए 26 फरवरी, 2013 को रूरल टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस इन्क्यूबेटर (आरटीबीआई) जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास अनुसंधान पार्क (आईआईटीएम) में एक इन्क्यूबेटर कक्ष है, के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं. आरटीबीआई के साथ मिलकर एक्ज़िम बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में नवोन्मेषी कार्य करने वाली कंपनियों की सहायता करेगा. आरटीबीआई ग्रामीण फोकस वाले कारोबारी उद्यमों की डिज़ाइन तैयार करने, उनका मार्गदर्शन करने और उन्हें संपोषित करने के मिशन के साथ एक अलाभकारी सोसायटी है. इसके संपोषण (इन्क्यूबेटर) क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वित्तीय समावेशन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सूक्ष्म उद्यम विकास तथा ग्रामीण जरूरतों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी समाधान शामिल हैं. इसने अब तक 26 कंपनियों को सहायता प्रदान की है.

एक्ज़िम बैंक अपने ग्रासरूट पहल तथा विकास (ग्रिड) कार्यक्रम के माध्यम से ऐसी भारतीय कंपनियों के संवर्धन पर विशेष जोर देता है जिनका ग्रामीण फोकस है. बैंक ने त्रिपुरा, ओडिसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में परिचालनरत/ कार्यरत कई कंपनियों तथा अलाभकारी संगठनों की निर्यात संभाव्यता बढ़ाने तथा सम्बद्ध शिल्पकारों/ कामगारों की आजीविका सुधारने में सहायता की है.

आरटीबीआई के साथ एक्ज़िम बैंक का सहयोग-ज्ञापन (एमओसी) उन कंपनियों के लिए नये अवसर खोलेगा जिन्हें उनके प्रारंभिक चरण में मार्गदर्शन तथा वित्तीय सहायता की जरूरत है. आरटीबीआई अपने इन्क्यूबेटीज़ के लिए निधीयन सुगम बनाने हेतु विभिन्न विकल्पों की संभावनाओं का पता लगा रहा है. नई कंपनियाँ अपने आकार तथा नगण्य अनुभव को देखते हुए बैंकों से कार्यशील पूंजी निधीयन प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं. आरटीबीआई द्वारा कंपनियों की जांच प्रक्रिया और निगरानी की जाएगी तथा एक्ज़िम बैंक इन कंपनियों के लिए वित्तीय सहायता देगा.

प्रो. प्रणब बर्धन ने एक्ज़िम बैंक का वार्षिक स्थापना दिवस व्याख्यान 2013 दिया

प्रो. प्रणब बर्धन, प्रोफेसर अर्थशास्त्र, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्केले ने 14 मार्च, 2013 को मुंबई में एक्ज़िम बैंक का वार्षिक स्थापना दिवस व्याख्यान दिया. उन्होंने ''व्यापार तथा विकास का सिद्धांत - भारतीय दृष्टिकोण'' विषय पर अपने विचार व्यक्त किये. डॉ. उर्जीत आर. पटेल, उप-गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की.

प्रो. बर्धन ने भारत के संदर्भ में ''करके सीखना'' मॉडल और ''शैशव उद्योग'' मॉडल के निहितार्थों का विश्लेषण किया. उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में कोई भी फर्म अपने कर्मचारियों को कम मजदूरी अदाकर अपनी निम्न उत्पादकता की भरपाई तो कर सकती है, किन्तु यदि उत्पाद की गुणवत्ता औसत से कम है तो वह फर्म अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में असफल हो जाएगी. प्रो. बर्धन ने इस बात पर जोर दिया कि उत्पादकता में सुधार के लिए भारत को घरेलू स्तर पर समन्वित नीतियां विकसित करनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि व्यापारिक लाभ से नई आयातित निविष्टियों तथा मौजूदा उत्पादों की नई किस्मों तक पहुंच बढ़ेगी. हालांकि व्यापार उदारीकरण के साथ औद्योगिक औसत उत्पादकता के बढ़ने से होने वाले बाजार पुनराबंटन से निम्न-उत्पादकता वाली कंपनियां उद्योग से बाहर हो जाएगी. इससे निम्न-उत्पादकता विनिर्माण क्षेत्र में लगे कई लोग गैर-व्यापारिक क्षेत्र तथा अनौपचारिक सेवाओं की ओर पलायन कर देंगे जिससे शेष अर्थव्यवस्था में औसत उत्पादकता में गिरावट आएगी. प्रो. बर्धन ने भारतीय श्रम कानूनों को लचीला बनाने की जरूरत पर बल दिया साथ ही उन्होंने बिजली, सड़क, ऋण, प्रबंधकीय तथा संगठनात्मक प्रशिक्षण जैसे कई अन्य मुद्दों का भी उल्लेख किया जिन्हें उत्पादकता बढ़ाने के लिए दूर किया जाना चाहिए.

एक्ज़िम बैंक द्वारा गोवा में ग्रामीण महिला शिल्पियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

एक्ज़िम बैंक ने गोवा में नारियल की खोपड़ी (कोकोनट शेल) के साथ काम कर रही ग्रामीण महिला शिल्पियों के लिए डिज़ाइन विकास प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया. इस पहल से निर्यात क्षमता उत्पन्न होने की उम्मीद है क्योंकि कार्यशाला में विकसित डिजाइनों को अंतर्राष्ट्रीय अपील मिलेगी. शिल्पियों को गोवा में 14 मार्च, 2013 से 23 मार्च, 2013 तक 10 दिन की अवधि के लिए कार्यशाला में प्रशिक्षित किया गया. कार्यशाला में 30 महिलाओं ने व्याख्यान, प्रदर्शन, प्रस्तुति, अनुभव आदान-प्रदान तथा चर्चा के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया और उन्होंने नारियल की खोपड़ी (शेल) का प्रयोग करते हुए लगभग 20 उपयोगी प्रोटोटाइप्स विकसित किये. एक्ज़िम बैंक ने ओंकार एन्ट्स एंड क्राफ्ट्स एसोसिएशन (ओएसीए), एक अलाभकारी स्वैच्छिक संगठन और दि एन्ट्स क्राफ्ट ट्रस्ट के साथ मिलकर कार्यशाला का आयोजन किया. यह संगठन गोवा में उपेक्षित शिल्पियों, विशेषकर महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है और वर्तमान में 560 से अधिक महिला शिल्पकार इसकी सदस्य हैं.

एक्ज़िम बैंक ने कार्यशाला के लिए डिज़ाइनरों तथा प्रशिक्षकों की सेवाओं के लिए दि एन्ट्स क्राफ्ट ट्रस्ट, बैंगलोर से संपर्क किया था. कार्यशाला में शिल्पियों के शिल्प तथा कौशल स्तर के आधार पर नई डिज़ाइन और बिक्री योग्य उत्पादों के विकास के माध्यम से उनकी आय-निर्माण क्षमता में सुधार लाने के लिए महिला शिल्पियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया. इस कार्यशाला से महिला शिल्पियों को अपने कौशल को बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण अवसर मिलेगा और लुप्त हो रही इस कला को बचाया जा सकेगा. कार्यशाला में नव-विकसित प्रोटोटाइप्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापक बाजार तथा अपील मिलने की उम्मीद है.

10 भारतीय रत्न एवं आभूषण बाजार के लिए उज्ज्वल संभावनाएं

रत्न एवं आभूषण उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है और भारत विश्व में तेजी से बढ़ते आभूषण बाजारों में से एक है. भारत में इसमें कीमती धातुओं, हीरे, मोती, कीमती तथा अर्ध-कीमती रत्नों और कृत्रिम आभूषणों की सोर्सिंग, प्रोसेसिंग, विनिर्माण और बिक्री शामिल है.

वर्ष 2011 में 933 टन से अधिक खपत और 2011 में सोने की वैश्विक खपत में लगभग 20 प्रतिशत हिस्से के साथ भारत विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है. सोने का अधिकांश आयात आभूषणों के उत्पादन में जाता है. भारत में सोने की खपत 2009 तथा 2011 में आई गिरावट को छोड़कर निरंतर बढ़ रही है. 2012 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान भी सोने की मुख्य खपत में 23 प्रतिशत की गिरावट आयी है. मांग में गिरावट के कुछ कारण स्वर्णकारों की हड़ताल, सोने के आयात में कमी के उद्देश्य से सोने पर आयात शुल्क दुगुना करना और वैकल्पिक निवेश अवसर हैं **(तालिका)**.

तालिका : भारत में सोने की खपत
(टन में)

अवधि	आभूषण	निवल खुदरा निवेश	कुल	कुल में % वृद्धि
2006	526.2	195.7	721.9	0.04
2007	551.7	217.5	769.2	6.55
2008	501.6	211.0	712.6	1.04
2009	442.4	136.1	578.5	-18.82
2010	657.4	348.9	1006.3	2.04
2011	567.4	366.0	933.4	-7.24
तीन तिमाहियां 2011	493.9	296.0	789.9	-22.5
तीन तिमाहियां 2012	412.9	199.1	612.0	

स्रोत : विश्व स्वर्ण परिषद

भारत सोने का मुख्यत: निवल आयातक है. भारत विनिर्माण प्रयोजनों के लिए सोने का आयात करता है और इसके एक हिस्से को आभूषणों के रूप में निर्यात करता है. भारत स्वर्ण आभूषण के लिए एक प्रमुख बाजार भी है क्योंकि स्वर्ण आयात का प्रमुख भाग देशी बाजार के लिए इस्तेमाल किया जाता है. भारत द्वारा अपरिष्कृत सोने का आयात मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड, जिसका 2011-12 के दौरान अपरिष्कृत स्वर्ण के कुल आयात में 52 प्रतिशत हिस्सा रहा, और उसके बाद यूएई (17.6 प्रतिशत) तथा दक्षिण अफ्रीका (11.5 प्रतिशत) से करता है.

भावी संभावनाएं:

भारत का रत्न एवं आभूषण क्षेत्र न्यून उत्पादन लागत, आभूषणों की डिज़ाइनिंग तथा कारीगरी के लिए अत्यंत कुशल, सस्ते तथा उत्कृष्ट कारीगरों के कारण विश्व में सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी है इस क्षेत्र को मजबूत सरकारी समर्थन भी प्राप्त है. भारत आभूषणों तथा अन्य विलासित उत्पादों के लिए एक विशाल उपभोक्ता बाजार के लिए रूप में उभर रहा है और इस प्रकार प्रमुख ब्रांडों को भारतीय बाजार में अपनी मौजूदगी स्थापित करने हेतु आकर्षक अवसर हैं.

उद्योग की निर्यात बढ़त और एकल ब्रांड रिटेल स्टोरों में 51 प्रशित तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने के सरकार के निर्णय के साथ भारत में बढ़ते देशी बाजार ने भारतीय बाजार में कई विदेशी खिलाड़ियों को आकर्षित किया है. भारत सरकार ने एकल ब्रांड रिटेल नीति के अंतर्गत भारत में स्टोर खोलने के लिए इटालियन आभूषण ब्रांड दमियानी के एफडीआई प्रस्ताव सहित तीन एफडीआई प्रस्तावों को अनुमोदित किया है.

उपभोक्ता मुख्यत: आभूषण के रूप में सोने के आकर्षण और बचत आय तथा मंहगाई के प्रभावों को समंजित करने इसके गुणों के कारण सोने की खरीद जारी रखेंगे. विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार, एशियाई मांग आने वाले दशकों में स्वर्ण बाजार की मुख्य संवाहक होगी जिसमें चीन तथा भारत मांग के उत्प्रेरक होंगे. 2011 के दौरान भारत तथा चीन द्वारा सोने की कुल खपत सोने की कुल वैश्विक मांग का 55 प्रतिशत रही.

भारत को ''अपरिष्कृत हीरे के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केन्द्र'' बनाने पर रिपोर्ट

भारत विश्व में सबसे बड़ा हीरा तराशी तथा पॉलिशिंग केन्द्र है जो किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन सिस्टम के सभी विनियमों को कार्यान्वित करते हुए उसका एक जिम्मेदार तथा सक्रिय सदस्य बने रहने के लिए प्रतिबद्ध है. पिछली कुछ तिमाहियों के दौरान भारत से हीरे के निर्यात में मंदी को देखते हुए वाणिज्य, उद्योग एवं वस्त्र मंत्रालय द्वारा विदेश व्यापार महानिदेशक डॉ. अनूप के पुजारी की अध्यक्षता में हीरे पर एक कार्य दल का गठन किया गया. कार्य-दल की कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

- बेनिन मूल्यांकन प्रक्रिया (बीएपी) के अंतर्गत लाभ की गणना करने की दर को 6 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करना.
- तराशे तथा पॉलिश किये गये हीरों के आयात के लिए 15 प्रतिशत शुल्क-मुक्त पुन: आयात कोटा.
- अपरिष्कृत हीरों के आयात तथा व्यापार के लिए विशेष अधिसूचित क्षेत्र की स्थापना.
- बैंकों द्वारा उद्योग को दिए गए डॉलर ऋणों के पुनर्वित्तपोषण के लिए 3.5 बिलियन यूएस डॉलर की निधि की स्थापना.
- उद्योग के लिए 2 प्रतिशत ब्याज सहायता योजना लागू करना, क्योंकि अधिकांश हीरा निर्माता कंपनियां मौजूदा योजना के दायरे में नहीं आती हैं.
- भारत में खोदे गए हीरों के लिए लाभकरण नीति परिभाषित करना.
- ₹ 200 करोड़ की प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) की स्थापना करना.
- हीरों के जिनेरिक संवर्धन के लिए उद्योग के साथ साझेदारी में निधि की स्थापना.
- निर्यात की लेन-देन लागत को कम करने के लिए प्रक्रिया संबंधी अन्य सुझाव.

वैश्विक निर्यात की तुलना में भारतीय निर्यात

डॉलर मूल्य की दृष्टि से भारत के निर्यात में 2001 से 2011 की अवधि के दौरान 85 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई और यह 43.9 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 301.5 बिलियन यूएस डॉलर हो गया. यह उल्लेखनीय है कि विश्व आयात की तुलना में भारत के निर्यात में इसी अवधि के दौरान 21.2 प्रतिशत की यौगिक वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई, जबकि विश्व आयात इसी अवधि में 11.1 प्रतिशत बढ़ा. पिछले दशक के दौरान भारत के निर्यात का एक मुख्य सकारात्मक पहलू विश्व आयात में भारत का बढ़ता हिस्सा रहा है. विश्व आयात में भारत का निर्यात हिस्सा 2001 के मात्र 0.7 प्रतिशत से बढ़कर 1.7 प्रतिशत हो गया है.

तथापि, विश्व आयात में भारत का निर्यात हिस्सा एक दशक के बाद भी सभी ब्रिक्स देशों में सबसे कम बना हुआ है. हालांकि 2001–2011 की अवधि के लिए निर्यात की सीएजीआर की दृष्टि से भारत के आंकड़े चीन (21.7 प्रतिशत) के बाद दूसरे स्थान पर हैं, अन्य दो राष्ट्र रूस और ब्राजील क्रमश: 17.1 प्रतिशत और 16 प्रतिशत हिस्से के साथ अधिक पीछे नहीं हैं.

उत्पादों की दृष्टि से 2011 में निर्यातित शीर्ष 5 उत्पादों में पेट्रोलियम सहित खनिज उत्पाद (63.1 बिलियन यूएस डॉलर), मशीनरी एवं परिवहन उपकरण (44.1 बिलियन यूएस डॉलर), प्रसंस्कृत उत्पाद सहित कृषि आधारित उत्पाद (37.8 बिलियन यूएस डॉलर) और वस्त्र एवं उत्पाद (25.4 बिलियन यूस डॉलर) शामिल हैं. वस्तुत: उत्पादों का यही समूह 2001 में शीर्ष 5 में शामिल था, हालांकि उनका क्रम भिन्न था जिसमें प्रसंस्कृत उत्पादों सहित कृषि आधारित उत्पादों के साथ वस्त्र तथा उनके उत्पाद उस समय निर्यात किये जाने मुख्य उत्पाद थे.

प्रसंस्कृत उत्पादों सहित कृषि आधारित उत्पादों की सीएजीआर 37.8 प्रतिशत के साथ सबसे तेजी से बढ़ती मद थी, उसके बाद पेट्रोलियम 35.1 प्रतिशत, मशीनरी एवं परिवहन उपकरण 26.4 प्रतिशत, औषधीय उत्पाद 23.5 प्रतिशत का स्थान था. यह उल्लेखनीय है कि कुल मिलाकर भारत से निर्यातित उच्च वृद्धि वाले इन उत्पादों ने विश्व आयात की तुलना में उच्चतर सीएजीआर दर्ज की. इस तथ्य को देखते हुए सीएजीआर की दृष्टि से भारत से निर्यातित शीर्ष 5 उत्पाद विश्व में आयातित शीर्ष 5 उत्पादों तथा विश्व मांग के अनुरूप हैं.

हालांकि विश्व आयात में भारत का निर्यात हिस्सा पिछले 10 वर्ष की तुलना में बढ़ा है, जिसमें रत्न एवं आभूषण में अच्छी वृद्धि हुई है. रत्न और आभूषणों का हिस्सा 2001 के 5.7 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 9.7 प्रतिशत हो गया है. विश्व आयात बाजार में निरंतर उच्च हिस्सा हासिल करने वाले अन्य भारतीय उत्पाद हैं : वस्त्र एवं उत्पाद (2.6 प्रतिशत से 3.9 प्रतिशत), प्रसंस्कृत उत्पाद सहित कृषि आधारित उत्पाद (1.6 प्रतिशत से 2.6 प्रतिशत), जूते एवं चमड़ा उत्पाद (1.8 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत), फार्मास्युटिकल्स, रसायन तथा खनिज उत्पाद, इन तीनों ने विश्व आयात में अपना हिस्सा बढ़ाकर 1.7 प्रतिशत कर लिया है. परिवहन उपकरण एक अन्य क्षेत्र है जिसने पिछले दशक में अच्छा बाजार हिस्सा हासिल किया है जिसका वर्तमान बाजार हिस्सा 1.3 प्रतिशत है **(तालिका)**.

तालिका : वैश्विक निर्यात की तुलना में भारत के निर्यात के क्षेत्रीय कार्य–निष्पादन का दशकीय विश्लेषण

	भारत का निर्यात							विश्व आयात				
मद	बिलियन यूएस डॉलर		सीएजीआर	उत्पाद हिस्सा (%)		विश्व में भारत का हिस्सा		बिलियन यूएस डॉलर		सीएजीआर	उत्पाद हिस्सा (%)	
	2001	2011	2001–11	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001–11	2001	2011
पेट्रोलियम सहित खनिज उत्पाद	**3.1**	**63.1**	**35.1**	**7.1**	**20.9**	**0.4**	**1.7**	**702.0**	**3663.1**	**17.9**	**11.1**	**20.2**
रत्न एवं आभूषण	**7.0**	**50.0**	**21.7**	**16.0**	**16.6**	**5.7**	**9.7**	**122.0**	**515.6**	**15.5**	**1.9**	**2.8**
मशीनरी एवं परिवहन उपकरण	**4.2**	**44.1**	**26.4**	**9.6**	**14.6**	**0.2**	**0.7**	**2705.5**	**6518.4**	**9.2**	**42.9**	**35.9**
पूँजीगत माल	*3.2*	*24.3*	*22.2*	*7.3*	*8.1*	*0.2*	*0.5*	*2002.1*	*4933.8*	*9.4*	*31.7*	*27.3*
इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	*1.3*	*11.7*	*24.6*	*3.0*	*3.9*	*0.1*	*0.5*	*907.0*	*2317.9*	*9.8*	*14.4*	*12.8*
मशीनरी	*1.6*	*10.8*	*21.0*	*3.6*	*3.6*	*0.2*	*0.5*	*900.7*	*2096.2*	*8.8*	*14.3*	*11.6*
ऑप्टिकल, फोटो उपकरण	*0.3*	*1.8*	*19.6*	*0.7*	*0.6*	*0.2*	*0.4*	*194.4*	*519.7*	*10.3*	*3.1*	*2.9*
परिवहन उपकरण	*1.0*	*19.9*	*34.9*	*2.3*	*6.6*	*0.1*	*1.3*	*703.3*	*1584.6*	*8.5*	*11.1*	*8.7*
पोत एवं अन्य तैरती संरचनाएं	*0.0*	*7.2*	*53.4*	*0.0*	*2.4*	*0.0*	*6.4*	*26.6*	*113.3*	*15.6*	*0.4*	*0.6*
विमान एवं उसके पुर्जे	*0.1*	*2.3*	*36.8*	*0.2*	*0.8*	*0.1*	*1.2*	*102.8*	*189.1*	*6.3*	*1.6*	*1.0*
रेलवे एवं ट्रामवे	*0.0*	*0.1*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.4*	*9.7*	*31.5*	*12.5*	*0.2*	*0.2*
रेलवे एवं ट्रामवे से भिन्न वाहन	*0.9*	*10.3*	*27.6*	*2.1*	*3.4*	*0.2*	*0.8*	*564.2*	*1250.7*	*8.3*	*8.9*	*6.9*
रसायन एवं उसके उत्पाद	**3.1**	**18.8**	**19.8**	**7.1**	**6.3**	**0.8**	**1.7**	**382.0**	**1130.3**	**11.5**	**6.1**	**6.2**
औषधि उत्पाद	**1.0**	**8.3**	**23.5**	**2.3**	**2.7**	**0.9**	**1.7**	**116.9**	**476.8**	**15.1**	**1.9**	**2.6**
वस्त्र एवं उत्पाद	**8.5**	**25.4**	**11.6**	**19.4**	**8.4**	**2.6**	**3.9**	**332.5**	**644.7**	**6.8**	**5.3**	**3.6**
धातु एवं उत्पाद	**2.8**	**21.2**	**22.3**	**6.4**	**7.0**	**0.7**	**1.6**	**388.5**	**1345.6**	**13.2**	**6.2**	**7.4**
कृषि आधारित एवं सम्बद्ध उत्पाद	**8.4**	**37.8**	**38.7**	**19.1**	**12.5**	**1.6**	**2.6**	**516.4**	**1482.6**	**11.1**	**8.2**	**8.2**
लकड़ी आधारित तथा पेपर उत्पाद	**0.3**	**1.5**	**18.3**	**0.7**	**0.5**	**0.1**	**0.4**	**220.3**	**422.5**	**6.7**	**3.5**	**2.3**
जूते एवं चमड़े	**2.0**	**5.6**	**10.3**	**4.6**	**1.9**	**1.8**	**2.5**	**109.5**	**224.9**	**7.5**	**1.7**	**1.2**
विविध उत्पाद	**3.4**	**26.0**	**22.7**	**7.7**	**8.6**	**0.5**	**1.5**	**715.2**	**1710.9**	**9.1**	**11.3**	**9.4**
सभी उत्पाद	**43.9**	**301.5**	**21.2**	**100.0**	**100.0**	**16.4**	**39.8**	**6312.9**	**18137.4**	**11.1**	**100.0**	**100.0**

स्रोत : आंकड़े आईटीसी, डब्ल्यूटीसी / अंकटाडा भारतीय एक्ज़िम बैंक शोध से प्राप्त किये गये.

12 पश्चिम आस्ट्रेलिया में निवेश अवसर

भारतीय कंपनियों के लिए पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में निवेश करने के लिए इससे बेहतर अवसर कभी नहीं रहा है. ऑस्ट्रेलिया के पावरहाउस राज्य में अवसरों की प्रचुरता है. ऑस्ट्रेलिया भारत के विदेशी निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य स्थान है. अप्रैल 1996 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान ऑस्ट्रेलिया में भारतीय निवेश की मात्रा 4.8 बिलियन यूएस डॉलर रही जो ऑस्ट्रेलिया को भारत के विदेशी निवेश के लिए एक अग्रणी गंतव्य स्थान बनाता है. वर्ष 2012-13 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में भारत का निवेश 1.3 बिलियन यूएस डॉलर रहा जो ऑस्ट्रेलिया को भारत के विदेशी निवेश के लिए सातवां सबसे बड़ा गंतव्य स्थान बनाता है. भारत भी 2012 में कुल 4.4 बिलियन यूएस डॉलर के दुतरफा व्यापार के साथ पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के सातवें सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरा है.

पश्चिम ऑस्ट्रेलिया को स्टैंडर्ड एंड पुअर्स तथा मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विसेज़ से ट्रिपल ए ऋण रेटिंग प्राप्त है. खनिज, तेल एवं गैस उत्पादन करने वाले विश्वस्तरीय संसाधन क्षेत्र के साथ प्रांत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और इसके 2013 में श्रेष्ठ निष्पादक अर्थव्यवस्था बनी रहने की उम्मीद है. पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के पास विपुल खनिज भंडार है और इसके तट पर वैश्विक रूप से महत्त्वपूर्ण ऊर्जा प्रांत हैं जिसके परिणामस्वरूप इस देश को संसाधन निष्कर्षण और प्रसंस्करण में मजबूत प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त है. पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की एशिया से गहन निकटता है जो इसे भारतीय निवेश के लिए एक रणनीतिक गंतव्य स्थान बनाता है. पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में एक प्रमुख परियोजना गोरगॉन तरल प्राकृतिक गैस परियोजना है.

पश्चिम ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 1996 में मुंबई में अपना कार्यालय खोला जो परस्पर कारोबारी संबंध व्यापार एवं निवेश तथा ऑस्ट्रेलिया में भारतीय निवेश को सुगम बनाता है. दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय निदेशक पीटर फॉर्बी, जो मुंबई में पदस्थापित हैं, भारत के साथ पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के संबंधों के भविष्य के बारे में काफी सकारात्मक हैं और उनका कहना है कि खनन, तेल एवं गैस तथा कृषि क्षेत्र में निवेश अवसरों की तलाश में कई भारतीय कंपनियों ने उनसे संपर्क किया है.

उनके अनुसार, भारतीय कंपनियों को सिर्फ संसाधन क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए क्योंकि वित्तीय सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, आईसीटी, पर्यावरण सेवा, भवन एवं निर्माण तथा पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार के अवसर हैं.

ऑस्ट्रेलिया में भारतीय निवेश का भौगोलिक वितरण यह दर्शाता है कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भारतीय निवेश शेष ऑस्ट्रेलिया में निवेश की तुलना में काफी कम है. पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के पास विपुल खनिज भंडार हैं और इसके तट पर वैश्विक रूप से महत्त्वपूर्ण ऊर्जा प्रांत है जिसके परिणामस्वरूप इस देश को संसाधन निष्कर्षण और प्रसंस्करण में मजबूत प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त है.

यथा मार्च 2013 को क्षेत्र में अनुमोदित कुछ परियोजनाओं में शामिल हैं : क्विनाना में सीएसबीपी की अमोनिया नाइट्रेट उत्पादन सुविधा का विस्तार, लगभग 350,000 टीपीए टेक्निकल अमोनिया नाइट्रेट (टैन) संयंत्र के निर्माण के लिए बुरूप नाइट्रेट्स पीटीवाई लि. नामक संयुक्त उद्यम, कैलगूर्ली में एंग्लोगोल्ड अशांति की स्वर्ण खनन परियोजना; पर्थ के दक्षिण में एमजेडआई की खनिज बालू खान; और पिलबारा में राज्य सरकार का अशबुर्टान उत्तर रणनीतिक औद्योगिक क्षेत्र (ऐनशिया).

पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में खनन, तेल एवं गैस क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं में कई भारतीय कंपनियों ने पहले से ही निवेश कर रखा है जो खनन उद्योग के लिए पॉलियूरेथन उत्पादों के उत्पादन और आईटी सेवाओं के प्रावधान के जरिए परिचालन कर रही हैं. ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायोग के अनुसार, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में कुछ मौजूदा भारतीय निवेशों में शामिल हैं :

- आदित्य बिड़ला मिनरल्स, जो ऑस्ट्रेलिया आधारित खनन कंपनी है तथा पश्चिम ऑस्ट्रेलिया तथा क्वींसलैंड में तांबे के उत्पादन तथा खोज पर फोकस करते हुए व्यापक तांबा खनन का कार्य करती है. आदित्य बिड़ला मिनरल्स आदित्य बिड़ला ग्रुप की एक कंपनी है और हिंडल्को इंडस्ट्रीज लि. के पास इसका आंशिक स्वामित्व है. तांबे की खान में उत्पन्न सांद्रणों को भारत में हिंडाल्को के स्वामित्व वाले कॉपर स्मेल्टर के लिए भेजा जाता है.
- अनुसंधान संगठन नेशनल आईटीसी ऑस्ट्रेलिया (एनआईसीटीए) तथा इनफोसिस ने कारोबार में प्रौद्योगिकी समस्याओं के बारे में सहयोग करने के लिए फरवरी 2013 को एक सौदे पर हस्ताक्षर किये हैं.
- भारत की सबसे बड़ी उर्वरक निर्माता कंपनी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लि. (इफ्को), और लीजेंड होल्डिंग्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फास्फेट रॉक अन्वेषक कंपनी ने एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं. इस करार में लीजेंड की फॉस्फेट परियोजनाओं में इफ्को द्वारा 100 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है.

पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में निवेश के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया पश्चिम ऑस्ट्रेलिया व्यापार एवं निवेश कार्यालय की वेबसाइट www.watoindia.in देखिए या peter.forby@dsd.wa.gov.au पर पीटर फॉर्बी से संपर्क करें.

निर्यात विपणन सेवाएं

जनवरी–मार्च 2013

फरवरी 2013 में एक्ज़िम बैंक ने विश्वेस्वरैया इंडस्ट्रियल ट्रेड सेंटर (वीआईटीसी), बेंगलुरू और राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थापन (एनआईडी) अहमदाबाद के साथ मिलकर बीदर, कर्नाटक में 37 बिदरीवेयर शिल्पकारों के लिए बारह दिवसीय 'डिज़ाइन विकास प्रशिक्षण कार्यशाला' का आयोजन किया. इस कार्यशाला का उद्देश्य बदलते समय और देशी/ अंतर्राष्ट्रीय बाजार आवश्यकताओं के साथ कदम मिलाकर चलने और शिल्प एवं डिज़ाइन प्रक्रिया के माध्यम से समसामयिक बाजारों के लिए उपयुक्त नये उत्पादों की एक श्रृंखला विकसित करना था. कार्यशाला में डिज़ाइन जागरूकता, उत्पाद विकास प्रक्रिया से संबंधित जानकारियां देने सहित पारंपरिक शिल्पकारों को नये रूप, पैटर्न, तकनीक तथा उत्पाद का प्रयोग करने के लिए अभिप्रेरित किया गया.

04–16 फरवरी, 2013 के दौरान आयोजित यह डिज़ाइन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम डिज़ाइन सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम का दूसरा चरण था जिसके जरिए एक्ज़िम बैंक बिदरी शिल्पकारों की निर्यातशीलता को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है. कार्यक्रम का पहला चरण अप्रैल 2012 में आयोजित किया गया था.

इस कार्यक्रम में कुल 37 शिल्पकारों को एनआईडी से वरिष्ठ संकाय सदस्यों द्वारा प्रशिक्षित किया गया. इस कार्यशाला से शिल्पकारों को उत्पादों की नई डिज़ाइन तथा विकास के माध्यम से बिदरीवेयर उत्पादों के बारे में अपनी समझ तथा गुणवत्ता बढ़ाने तथा आय स्तर में सुधार लाने में सहायता मिली. शिल्पकारों को घरेलू उपयोग तथा उपयोगिता के विभिन्न पैटर्नों की डिज़ाइन तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया. इसमें फ्रिज मैग्नेट, विजिटिंग कार्ड बॉक्स, टेबल घड़ी (रोलिंग व पैसली घड़ी), पेन होल्डर, बुक मार्क, क्लिप बोर्डपिन, टाई हैंगर, बुक एंड्स, पेन ड्राइव, लेजर प्वॉइंटर, बॉक्स के साथ कोस्टर, टी–लाइट्स, मोमबत्ती स्टैंड, एकल हुक, नैपकिन रिंग, लोहे की तिपाई, परदा झालर, डोर हैंडल, कैबिनेट हैंडल, कैबिनेट नॉब, डिस्प्ले प्लेट, मोबाइल हैंगिंग तथा कैनन जैसी उपहार सामग्रियां आदि प्रमुख हैं. इससे बिदरी कला को जीवित रखने में भी मदद मिलेगी.

चरण–।। कार्यशाला के अंतर्गत, एनआईडी संकाय ने विभिन्न डिजाइनें प्रोटोटाइप तैयार किये जिनसे धातु, लकड़ी के मिश्रण या शीट पर कार्य करते हुए हल्के बिदरीवेयर बनाने में सहायता मिली. चांदी का सीमित प्रयोग करने और उत्पादन लागत की बचत करने के लिए समसामयिक डिजाइनों का प्रयोग किया गया.

एक्ज़िम बैंक अपनी निर्यात विपणन सेवा के माध्यम से भारतीय कंपनियों में निर्यात क्षमता उत्पन्न करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए संवर्धनात्मक भूमिका अदा करता है. एक्ज़िम बैंक विदेशों में अवसरों की पहचान करने और भारतीय निर्यातक फर्मों की उनके उत्पादों एवं सेवाओं के लिए समुद्रपारीय वितरक(कों) / क्रेता(ओं) / साझेदारों का पता लगाने में सक्रिय रूप से सहायता करके उनके भूमंडलीकरण प्रयासों में उनकी सहायता करता है.

एक्ज़िम केन्द्र कार्यकलाप

विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें :
सुश्री दीपाली अग्रवाल
उप महाप्रबंधक
भारतीय निर्यात–आयात बैंक
मुंबई
फोन : (022) 22172713
ई–मेल : deepali@eximbankindia.in

जनवरी–मार्च 2013

एक्ज़िमिअस केन्द्र और अर्जेंटिना के दूतावास ने चेन्नई में 29 जनवरी, 2013 को 'अर्जेंटिना के साथ कारोबार' विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया. कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में अर्जेंटिना में उपलब्ध व्यापार एवं निवेश अवसरों और एक्ज़िम बैंक के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना था. अर्जेंटिना के उप महादूत श्री एलेजैंड्रो जोथनर मेयर ने प्रतिभागियों को संबोधित किया.

एक्ज़िम बैंक ने 30 जनवरी, 2013 को कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया. इसमें 'एक्ज़िम बैंक के उत्पाद एवं सेवाएं' विषय पर प्रस्तुति दी गई.

एक्ज़िमिअस केन्द्र और वीआईटीसी ने 18–23 फरवरी, 2013 के दौरान ''निर्यात प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम'' का आयोजन किया. कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को निर्यात तथा आयात व्यापार के अवसरों, निबंधनों एवं शर्तों से परिचित करना था.

भावी कार्यक्रमों में शामिल हैं :

- अरब देशों के साथ कारोबार, और
- विश्व व्यापार संगठन कार्यक्रम : भारत द्वारा हस्ताक्षरित विभिन्न क्षेत्रीय व्यापार करारों (आरटीए) के आलोक में कर्नाटक राज्य के सेवा आपूर्तिकर्ताओं के लिए उभरते कारोबारी अवसर, और 'कर्नाटक के निर्यातकों (माल क्षेत्र) के लिए डब्ल्यूटीओ प्रावधानों के परिणाम' विषय पर कार्यक्रम. ये कार्यक्रम वीआईटीसी तथा एफआईईओ के साथ संयुक्त रूप में आयोजित किये जाएंगे.

विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें :
श्री टी. वी. राव
सलाहकार – एक्ज़िमिअस केन्द्र
भारतीय निर्यात–आयात बैंक
बेंगलुरू
फोन : (080) 25589106
ई–मेल : eximius@eximbankindia.in

14 देशों का सूक्ष्मावलोकन

केन्या

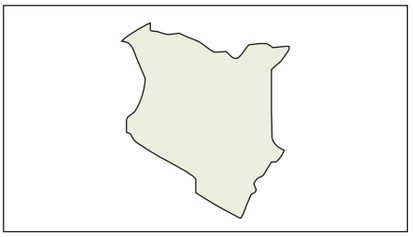

वर्ष 2012 में 4.3 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने के बाद केन्या 2013 में 5 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करने की अच्छी स्थिति में है क्योंकि घटती मुद्रास्फीति से आर्थिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त होने की संभावना है. वर्ष 2010 को छोड़कर हालिया वर्षों में देश को राजनीतिक, आर्थिक या मौसम संबंधी आघातों का सामना करना पड़ा है. केन्या में निजीकरण को जनवरी 2013 में गति मिली जब संसद ने तीन अग्रणी होटलों और केन्या वाइन एजेन्सीज (केडब्ल्यूएएल) में हिस्सेदारी बेचने का अनुमोदन किया. जनवरी में 10 बिलियन यूएस डॉलर के कोंजा टेक्नोलॉजी शहर का शुभारंभ भी सॉफ्टवेयर विकास के लिए एक मुख्य हब बनने के केन्या के अभियान का संकेत देता है. कवाले मिनरल सैंड्स प्रोजेक्ट के पूरा होने पर यह केन्या की पहली आधुनिक खान बन जाएगी जिससे प्रति वर्ष 250 मिलियन यूएस डॉलर की निर्यात आय प्राप्त होगी और जीडीपी में खनन क्षेत्र का योगदान मौजूदा 0.7 प्रतिशत से बढ़कर 1.7 प्रतिशत हो जाएगा.

अज़रबैज़ान

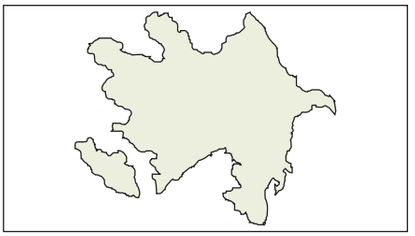

इस देश ने वर्षों तक स्वर्ण, एथनॉल तथा नवीकरणीय ऊर्जा सहित प्राकृतिक संसाधनों की विपुल आपूर्ति का लाभ उठाया है, लेकिन हाल ही में इसने परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा प्रौद्यागिकी के क्षेत्र में भी विशाखन किया है. 2010 से अंतर्निहित आर्थिक गतिकी में उल्लेखनीय बदलाव हुआ है क्योंकि गैर-तेल क्षेत्र ने वृद्धि के मुख्य संवाहक के रूप में तेल क्षेत्र को प्रतिस्थापित कर लिया है. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2013 में अज़रबैज़ान में गैर-तेल जीडीपी में 9 प्रतिशत की वृद्धि का पूर्वानुमान किया है. देश में गैर-तेल निवेश बढ़ रहे हैं. सैमसंग इंजीनियरिंग और एसओसीएआर कार्बामाइड प्लांट के निर्माण के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं. इस प्लांट से मुख्यत: नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन होगा जिसका उपयोग देशी मांग को पूरा करने और निर्यात के लिए भी किया जाएगा.

पेरू

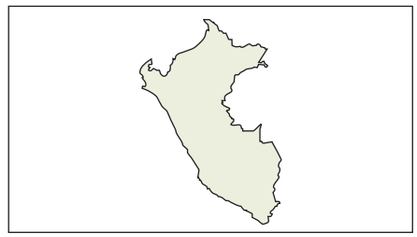

नब्बे के दशक के पूर्वार्द्ध से पेरू ने सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की है जिसमें से राजकोषीय सुधार, व्यापार खुलापन, विनियम दर में लचीलापन, वित्तीय उदारीकरण, बाजार संकेतों पर अधिक निर्भरता और सुदृढ़ रिज़र्व के निर्माण सहित विवेकपूर्ण मौद्रिक नीति मुख्य घटक रहे हैं. विदेशी निवेश मुख्यत: खनन, हाइड्रोकार्बन तथा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में हैं. साथ ही, पण्यों में तेजी से भी निर्यात आय से कर राजस्व में वृद्धि हुई है. सार्वजनिक निवेश रेकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है और सभी प्रकार के उपभोक्ता उत्पादों के लिए देशी बाजार बढ़ा है. यह औसतन 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से आठ वर्षों (2004-2012) की वृद्धि का परिणाम है. पेरू के खनन क्षेत्र में निवेश पिछले वर्ष की 18 प्रतिशत की तुलना में 2013 में 16 प्रतिशत रहने की उम्मीद है. किन्तु बड़ी खनन परियोजनाओं के विरोध चिंताजनक है जैसाकि सामाजिक अशांति और विरोध से परिलक्षित होता है जिनके चलते काजमार्का में 5 बिलियन यूएस डॉलर निवेश की मिनास कांगा परियोजना में विलम्ब हुआ है.

मोरोक्को

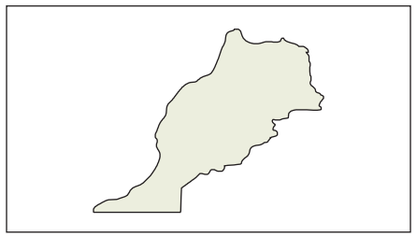

मोरोक्को के पास सिर्फ 2 मिलियन बैरल तेल और 43 बिलियन क्यूबिक फीट गैस का प्रमाणित भंडार है जिससे यह उत्तर अफ्रीकी क्षेत्र में सबसे बड़ा हाइड्रोकार्बन आयातक हो गया है. देश अपनी ऊर्जा खपत के 62 प्रतिशत के लिए आयातित तेल पर निर्भर करता है और अन्य 30 प्रतिशत कोयले का आयात है. फलस्वरूप देश में प्रमुख तेल एवं गैस परियोजनाओं की कमी है. अधिकांश परियोजनाएं देश भर में फैले छोटे-छोटे खोज ब्लॉक हैं. तथापि, मोरक्को में वर्तमान में दो प्रमुख तेल एवं गैस परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं. मोरक्को फॉस्फेट का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक है जो सरकारी कंपनी ऑफिस शेरफिन डेस फॉस्फेट (ओसीपी) द्वारा विकसित किया जा रहा क्षेत्र है. ब्राजील की बंग सहित कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने ओसीपी के साथ साझेदारी सौदे पर हस्ताक्षर किये हैं.

श्री लंका

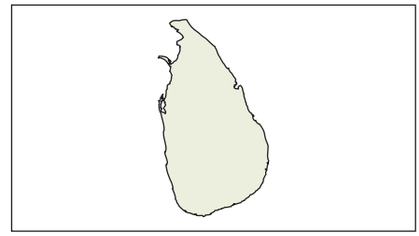

श्री लंकाई अर्थव्यवस्था 2009 के मध्य में नागरिक संघर्ष की समाप्ति के बाद उछाल पर है और 2012 में यह अर्थव्यवस्था दक्षिण एशिया में तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी जिसमें आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई. भविष्य के लिए विज़न 8 प्रतिशत से अधिक वार्षिक वृद्धि दर हासिल करना है और इस प्रकार मौजूदा प्रति व्यक्ति आय को 2016 तक लगभग दुगुना 4000 यूएस डॉलर तक करने का लक्ष्य है. देश की जोरदार आर्थिक वृद्धि को भुनाने के लिए सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ श्री लंका अंतर्देशीय वित्तीय बाजार में निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए पूँजी बाजार के विकास और विनियमन के लिए प्रमुख कदम उठा रहा है. वर्ष 2013 के लिए 1.5 बिलियन यूएस डॉलर के एफडीआई का लक्ष्य रखा गया है. विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमन में हालिया छूट इस दिशा में एक कदम है. देश ने पोर्ट, पर्यटन तथा वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में निवेश अवसरों की तलाश करने के लिए भारतीय कारोबार समुदाय को आमंत्रित किया है.

पौंड स्टर्लिंग (जीबीपी)

2013 के दौरान पौंड अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1.5847 से 1.5166 की लंदन बंद दरों के अनुसार तेजी से कमजोर हुआ. इसका मुख्य कारण बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को मज़बूत वृद्धि की राह पर लाने के उद्देश्य से अपने मौद्रिक रुख में अधिक आक्रमक होना रहा है. इस धारणा की पुष्टि पहले मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद जारी बयान और उसके बाद तिमाही मुद्रास्फीति रिपोर्ट में हुई है. दोनों रिपोर्टों में मुद्रास्फीति की दर के प्रति उदासीनता दिखाई गई हैं जिसके दो वर्ष की संपूर्ण पूर्वानुमान अवधि के दौरान 2 प्रतिशत के सरकारी लक्ष्य स्तर से ऊपर रहने की उम्मीद है.

बैंक ऑफ इंग्लैंड अब मुद्रास्फीति की कीमत पर आर्थिक वृद्धि पर विशेष ध्यान दे रहा है. इसके अलावा, बैंक ऑफ इंग्लैंड इसी रणनीति के हिस्से के रूप में कमजोर पौंड को प्रोत्साहित करने का इच्छुक भी दिखाई दे रहा है. कमजोर पौंड से अंतत: निर्यात को कुछ बढ़ावा मिलेगा किंतु यूके के निर्यात संमिश्र, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को निर्यात पर उच्च निर्भरता और वित्तीय सेवाओं के निर्यात को देखते हुए इस तेजी के मूर्त रूप लेने की संभावना कम ही है.

यूके की सॉवरिन ऋण रेटिंग को शीर्ष AAA से घटकर AAa करने और आउटलुक को स्टेबल करने के मूडीज़ के निर्णय से भी पौंड कमजोर हुआ. एस एंड पी तथा फिच भी आगामी महीनों में मूडीज़ का अनुसरण कर सकते हैं. कुछ ही AAA अवसरों की उपलब्धता को देखते हुए पौंड के लिए तात्कालिक परिणाम महत्त्वपूर्ण नही है. अन्य AA सॉवरिन देशों द्वारा अपने राजकोषीय सुधारों का कोई भी प्रयास पौंड को अतिसंवेदनशील स्थिति में छोड़ देगा. 31 मार्च, 2013 को पौंड 1 जीबीपी = 1.5206 यूएस डॉलर की दर पर उद्धृत हो रहा था.

ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (एयूडी)

ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (आरबीए) की मौद्रिक नीति से फरवरी के प्रारंभिक भाग में कुछ समर्थन मिला जिसमें यह विश्वास व्यक्त किया गया कि उसकी मौद्रिक नरमी का वास्तविक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है. तथापि, यद्यपि आरबीए मौद्रिक नीति के वर्धित समर्थन के लिए विश्वस्त है किन्तु देशी अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम बना हुआ है तथा कोई अप्रत्याशित कमजोरी संभवत: और नरमी में तब्दील हो सकती है.

उच्च ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और निम्न ब्याज दरें आरबीए के लिए निरंतर चिंता का विषय है. निरंतर उच्च ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ने आरबीए को ब्याज दरों में अधिक आक्रमक ढंग से कटौती करने के लिए बाध्य किया है और निम्न ब्याज दरों के चलते उपभोक्ता विश्वास तथा आवास की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं. कारोबारी स्थितियां बहुत कठोर बनी हुई हैं, किन्तु वर्तमान लाभ रिपोर्टिंग से पता चलता है कि कई कंपनियां लागत से ऊपर कमा रही हैं और मांग में एक बार तेजी आने पर अच्छी स्थिति में हो जाएंगी. यूएस में मात्रात्मक नरमी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को सामान्य स्तर पर लाने में सहायक हो सकती है. लेकिन जब तक खनन सम्बद्ध निवेश तथा रोजगार से हटकर अर्थव्यवस्था को पुनर्संतुलित करने के व्यापक साक्ष्य दिखाई नहीं देते हैं, आरबीए मौद्रिक नीति पर हॉकिश बॉयस का संकेत देने में अनिच्छुक रहेगा. जोखिमों के संतुलन के बारे में बदलती अवधारणाओं के चलते बाजार भविष्य में अब ब्याज दरों में सिर्फ एक और कटौती की उम्मीद करता है.

आरबीए पिछले 18 महीनों के दौरान ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की स्थिरता और ऑस्ट्रेलिया की व्यापार स्थिति में 17 प्रतिशत की तीव्र गिरावट के बीच असंगति को रेखांकित करता रहा है. ऑस्ट्रेलिया में मिश्रित देशी मांग स्थिति को देखते हुए बाजार ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में और गिरावट की उम्मीद करता है. 31 मार्च, 2013 को ऑस्ट्रेलियाई डॉलर पर 1 एयूडी = 1.0415 यूएस डॉलर पर ट्रेड हो रहा था.

दक्षिण कोरियाई वोन (केआरडब्ल्यू)

कोरिया के देशी तथा विदेशी दोनों बाजारों में हालिया हलचल के बावजूद उसे बाजार की अल्पकालिक अस्थिरता की कीमत पर निर्बाध परिचालन करने के अपने पुराने सिद्धांतों से हटकर फॉरेक्स नीति दृष्टिकोण में महत्त्वपूर्ण बदलाव करने की आवश्यकता है. पार्क प्रशासन की फॉरेक्स नीति पर बाजार में भ्रम है और उस पर बहस चल रही है.

हाल तक व्यापक रूप से यह माना जाता था कि पार्क प्रशासन केआरडब्ल्यू के मूल्य में और वृद्धि के पक्ष में होगा. तथापि, स्थानीय मीडिया की कई हालिया रिपोर्टें बताती हैं कि पार्क प्रशासन टॉबिन कर या वित्तीय लेन-देन कर जैसे उपायों के माध्यम से कमजोर स्थानीय मुद्रा की वकालत करके 'मुद्रा युद्ध' में शामिल हो सकता है. बाजार की राय में, इनमें से कोई भी नीति सही विकल्प नहीं है और इससे कुछ घटित होने वाला भी नहीं है. वस्तुत:, बाजार पार्क प्रशासन से फॉरेक्स नीति में किसी भारी परिवर्तन की अपेक्षा नहीं करता है. इस प्रकार, बाजार बीओके से मार्जिन में अल्पकालिक अस्थिरता को दूर करते हुए बाजार को विनिमय दरों का निर्धारण करने की अनुमति जारी रखने की अपेक्षा रखता है.

जैसाकि उम्मीद थी, बीओके ने फरवरी की एमपीसी बैठक में नीतिगत दर को 2.75 प्रतिशत पर बनाए रखने का निर्णय लिया, यद्यपि, प्रमुख मुद्रास्फीति की दर लक्ष्य दायरे (2.5 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत) के निचले स्तर से बहुत कम है और 2014 की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि के वर्ष-दर-वर्ष अधार पर लगभग 1-2 प्रतिशत पर मंद रहने की संभावना है. बीओके को उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था में सामान्य सुधार होगा और 2.5 प्रतिशत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के साथ 2.8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि हासिल होगी. 31 मार्च 2013 को दक्षिण कोरियाई वॉन 1 यूएस डॉलर = 1111.9 केआरडब्ल्यू पर ट्रेड हो रहा था.

तीसरी दुनिया के देशों में व्यापार : अद्यतन प्रवृत्तियां

विकासशील देश वर्तमान में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में आर्थिक कार्यकलापों तथा व्यापार में उच्चतर वृद्धि दर्शाते हुए क्षेत्रीय तथा वैश्विक वृद्धि के संवाहक के रूप में निरंतर उभरे हैं. वैश्विक व्यापार विन्यास में तीसरी दुनिया के देशों को बढ़ता महत्व वैश्विक पण्य निर्यात में विकासशील बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते हिस्से से प्रतिबिम्बित होता है जो 2001 के 32.5 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में लगभग 48 प्रतिशत हो गया है, जबकि विकसित बाजार अर्थव्यवस्थाओं का अनुरूपी हिस्सा इसी अवधि के दौरान 66 प्रतिशत से घटकर 52 प्रतिशत रह गया है **(चार्ट)**.

चार्ट : वैश्विक निर्यात में विकासशील तथा विकसित बाजार अर्थव्यवस्थाओं के हिस्से में प्रवृत्तियां (%)

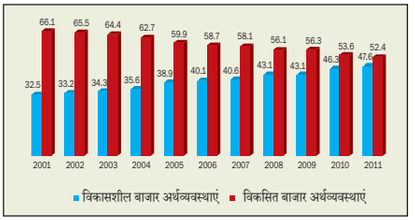

स्रोत : आईटीसी, ट्रेड मैप

तीसरी दुनिया के देशों में व्यापार की प्रवृत्तियां

2001 से 2011 के दशक के दौरान तीसरी दुनिया के देशों का निर्यात 2001 के 809.5 बिलियन यूएस डॉलर से तेजी से बढ़कर 3.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो गया जिसमें 17 प्रतिशत की सीएजीआर की वृद्धि दर्ज हुई है. परिणामस्वरूप विकासशील देशों के वैश्विक निर्यात के प्रतिशत के रूप में तीसरी दुनिया के देशों में अंत: निर्यात 2001 के 41 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में लगभग 46 प्रतिशत हो गया, जबकि विकासशील देशों के वैश्विक आयात के प्रतिशत के रूप में तीसरी दुनिया के देशों में अंत: आयात का हिस्सा इसी अवधि के दौरान 44 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर 52 प्रतिशत से अधिक हो गया जो तीसरी दुनिया के देशों में आयात सोर्सिंग की बढ़ती प्रवृत्ति का द्योतक है.

तीसरी दुनिया के देशों के बीच परस्पर सहयोग वैश्विक वृद्धि के संवाहक के रूप में निरंतर महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है. तीसरी दुनिया को विकास एजेंडा के लिए मुख्य व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया जा रहा है. तीसरी दुनिया के देशों के बीच परस्पर सहयोग सतत् आर्थिक विकास के उनके वैयक्तिक तथा सामूहिक लक्ष्य में विकासशील तथा परिवर्तनशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए व्यवहार्य अवसर प्रदान करता है. इस प्रकार, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में घनिष्ठ आर्थिक तथा व्यापार संबद्धताएं परस्पर लाभदायी स्थिति सिद्ध हो सकती हैं. दक्षिणी अर्थव्यवस्थाओं में मजबूत आर्थिक अनुपूरकता ने द्विपक्षीय व्यापार की तीव्र वृद्धि तथा गहनता को अनिवार्यत: रेखांकित किया है.

तीसरी दुनिया के देशों के बीच व्यापार तथा सहयोग में सामंजस्य स्थापित करना इन देशों के विकास को बनाए रखने के लिए महत्त्वपूर्ण है. तीसरी दुनिया के देशों की जोरदार वृद्धि वैश्विक अर्थव्यवस्था की सतत् वृद्धि के लिए नई प्रेरक-शक्ति प्रदान करेगी जो न केवल विकासशील देशों के लिए बल्कि औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी लाभदायक होगी क्योंकि तीसरी दुनिया के देशों में तीव्र मांग सभी के लिए व्यापारिक अवसर उत्पन्न करेगी.

पांचवा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

ब्रिक्स पांच उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह अर्थात् ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका के लिए एक संक्षिप्त रूप है. ब्रिक्स साझा अवसरों तथा सामान्य चुनौतियों के साथ एक विशिष्ट समूहन है. सितंबर 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर न्यूयार्क में ब्राजील, रूस, भारत तथा चीन के विदेशी मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान स्थापित इस समूह ने एक लम्बा सफर तय किया है और परामर्श तथा सहयोग के लिए कई व्यवस्था-तंत्र विकसित किये हैं. दक्षिण अफ्रीका 2010 में इस समूह में शामिल हुआ और इसने अप्रैल 2011 में सान्या, चीन में आयोजित तीसरे शिखर सम्मेलन में भाग लिया.

पांचवा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 'ब्रिक्स तथा अफ्रीका - एकीकरण एवं औद्योगिकीकरण हेतु साझेदारी' विषय पर केन्द्रित था. इसे 26-27 मार्च, 2013 के दौरान डरबन में आयोजित किया गया. इस शिखर सम्मेलन में बहुपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से ब्राजील गणराज्य, रूसी परिसंघ, भारत गणराज्य, चीन जन गणराज्य तथा दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के नेताओं ने भाग लिया. शिखर सम्मेलन ने, जो विश्व जनसंख्या के 45 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है, अफ्रीकी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के संवर्धन, ब्रिक्स की अगुआई में विकास बैंक की स्थापना, ब्रिक्स थिंक टैंक और ब्रिक्स कारोबार परिषद सहित सहयोग के अन्य कई क्षेत्रों पर फोकस किया.

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम भारत) ने अपनी स्थापना से ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ, विशेषकर तीसरी दुनिया के देशों के साथ भारत के बढ़ते एकीकरण में उत्प्रेरक की भूमिका अदा की है. एक्ज़िम भारत ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग व्यवस्था के अंतर्गत नामित सदस्य विकास बैंक है. क्षेत्रीय व्यापार को सुगम बनाने तथा बढ़ावा देने के लिए 1996 में स्थापित एशियाई एक्ज़िम बैंक फोरम और तीसरी दुनिया के देशों में वर्धित व्यापार तथा निवेश सहयोग को संपोषित करने के लिए 2006 में स्थापित एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं का वैश्विक नेटवर्क (जी-नेक्ज़िड) भी इस दिशा में बैंक की कुछ पहलें हैं.

इसमें प्रकाशित समाचार और जानकारी ऐसे विभिन्न स्रोतों/माध्यमों से एकत्रित की गई है जो अपने आप में प्रामाणिक हैं. प्रकाशित सामग्री की प्रामाणिकता को बनाये रखने में पूरी सावधानी बरती गई है फिर भी इस प्रकार की जानकारी की प्रामाणिकता और यथातथ्यता की कोई जिम्मेदारी एक्ज़िम बैंक की नहीं है.

नोट : भारतीय रुपये का उल्लेख करोड़ और लाख में किया गया है -

1 करोड़ : 10 मिलियन

1 लाख : 100 हजार

भारतीय निर्यात-आयात बैंक,
केन्द्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र कॉम्प्लेक्स,
कफ़ परेड, मुंबई - 400 005.
दूरभाष : 91 - 22 - 2217 2600
फैक्स : 91 - 22 - 2218 2572
ई-मेल : cag@eximbankindia.in
वेबसाइट : www.eximbankindia.in

संपर्क नंबर : अहमदाबाद : 079 2657 6852, बैंगलूरु : 080 2558 5755, चंडीगढ़ : 0172 2641 910, चेन्नै : 044 2852 2830, गुवाहाटी: 0361 2237607, हैदराबाद : 040 2330 7816, कोलकाता : 033 2289 1728, मुंबई : 022 2282 3320, नई दिल्ली : 011 2347 4800, पुणे : 020 2640 3000

अदिस अबाबा : + 251 116-630079, डकार : + 22133-8232849, दुबई: + 9714-3637462, जोहॉनिस्बर्ग : + 2711-3265103, लंदन : + 44 02-73538830, सिंगापुर: + 65 65-326464, वॉशिंग्टन डी.सी. : + 1 202-2233238.